घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 192- गुरूवार 14 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सक्षिप्त समाचार

सीबीएसई 12वीं का परिणाम घोषित 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी पास लड़कियों ने फिर मारी बाजी

नई दिल्ली,13 मई 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19 प्रतिशत कम है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 17,80,365 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 17,68,818 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 15,07,109 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। पास प्रतिशत में 3.19 प्रतिशत की कमी आई, जो 2025 के 88.39 प्रतिशत से घटकर 2026 में 85.20 प्रतिशत हो गया। सीबीएसई के अनुसार लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86 रहा, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस तरह लड़कियों ने लड़कों से 6.73 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवार प्रदर्शन में त्रिवेंद्रम क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां 95.62 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। इसके बाद चेन्नई, बेंगलुरु और विजयवाड़ा क्षेत्र का स्थान रहा। दिल्ली पश्चिम क्षेत्र का परिणाम 92.34 प्रतिशत और दिल्ली पूर्व क्षेत्र का परिणाम 91.73 प्रतिशत रहा। ओवरऑल दिल्ली क्षेत्र का पास प्रतिशत 91.97 प्रतिशत दर्ज किया गया जबकि प्रयागराज में सबसे कम 72.43 प्रतिशत पास प्रतिशत रहा।

अमूल ने देशभर में दूध की कीमतें दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाई,नई दरें आज से लागू

नई दिल्ली,13 मई 2026। अमूल ने बुधवार को बढ़ती लागत के कारण पूरे भारत में दूध की कीमतें दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की। नई दरें आज लागू होंगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) अमूल ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बेचती है। पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी एक मई, 2025 को की गई थी। जीसीएमएमएफ ने बयान में कहा कि उसने ''पूरे भारत में दूध की कीमतें आज दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं।'' उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी लगभग 2.5-3.5 प्रतिशत प्रति लीटर की है, जो औसत खाद्य महंगाई दर से कम है। जीसीएमएमएफ ने कहा, ''कीमतों में यह बढ़ोतरी दूध के परिचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है। इस साल पशु आहार, दूध की पैकेजिंग सामग्री और ईंधन की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है।'' इस सहकारी संस्था ने बताया कि उसके सदस्य संघों ने भी किसानों से दूध खरीदने की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम वसा (फैट) की बढ़ोतरी की है, जो मई, 2025 की तुलना में 3.7 प्रतिशत अधिक है।
जीसीएमएमएफ भारत में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन:फेफड़े में खून का थक्का जमने से कार्डिएक अरेस्ट आया

लखनऊ,13 मई 2026। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीसी पांडेय के मुताबिक, जब प्रतीक को लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी। हार्ट भी रुक चुका था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार, कार्डिएक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। बॉडी पर चोट के 6 निशान थे, जो पुराने हैं। विसरा सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक का शव उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है।

केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ की सतही कोयला गैसीकरण योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली,13 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सतही कोयला (लिग्नाइट) गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश में सतही कोयला (लिग्नाइट) को गैस में बदलने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन सतही कोयले का गैसीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे बहुत बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि भारत के पास लगभग 200 साल का कोयला भंडार है और अब इसका उपयोग गैस बनाने में किया जाएगा। इस योजना से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। गैसीकरण से देश की ऊर्जा निर्भरता कम होगी और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), यूरिया, अमोनिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी। उल्लेखनीय है कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है, जिसमें लगभग 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट शामिल है। कोयला देश की ऊर्जा खपत का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा करता है। गैसीकरण से कोयला और लिग्नाइट को 'सिंथेसिस गैस' (सिंगैस) में बदला जाता है, जिसका उपयोग ईंधन और रसायन बनाने में किया जाता है। इससे भारत को एलएनजी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत नए सतही कोयला गैसीकरण संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संयंत्र और मशीनरी की लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजनाओं का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से होगा। किसी एक परियोजना को अधिकतम 5 हजार करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। किसी एक उत्पाद के लिए अधिकतम 9 हजार करोड़ रुपये और किसी एक कंपनी समूह के लिए अधिकतम 12 हजार करोड़ रुपये तक की सीमा तय की गई है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने कोयला लिंकिंग की अवधि को भी 30 साल तक बढ़ा दिया है ताकि निवेशकों को दीर्घकालिक नीति का भरोसा मिल सके। इस योजना से देशभर में लगभग 25 परियोजनाओं के ज़रिए 50 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे हर साल लगभग 6 हजार 3 सौ करोड़ रुपये का राजस्व भी उत्पन्न होगा।

किसानों की आय, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा को नई ताकत देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट द्वारा लिए गए चार प्रमुख निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फैसले देश में विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कुल 3,18,165 करोड़ रुपये के चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन, कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा और अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा सेमी हाईस्पीड डबल रेल लाइन परियोजना शामिल हैं। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि देशभर के किसान भाई-बहनों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए हम निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा।

सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना भी मंजूर

केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके लिए किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं,सरकार ने कोल गैसिफिकेशन योजना के लिए 37,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आइए कैबिनेट के अहम फैसले जानते हैं। सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज में की गई है। इसकी एमएसपी पिछले साल के मुकाबले 622 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। इसके अलावा कपास में 557 रुपये, नाइजरसीड में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये और ग्रेड ए का एमएसपी 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अरहर का एमएसपी 8,450, मूंग का 8,780 और उड़द का 8,200 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। ईरान युद्ध संकट से उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 10 करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन क्षमता विकसित की जाए,ताकि कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर निर्भरता कम हो,घरेलू संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने। कोल गैसिफिकेशन ऐसी तकनीक है, जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय सीमित ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। इससे निकलने वाली गैस को सिंथेटिक गैस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मिथेनॉल, फर्टिलाइजर, अमोनिया समेत कई तरह के उद्योगों में किया जाता है। योजना का उद्देश्य 2030 तक कोयले से 100 मिलियन टन गैस का उत्पादन करना है। सरकार संयंत्र और मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

एन. रंगासामी 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ में मौजूद रहे

तिरुवनंतपुरम/पुडुचेरी,13 मई 2026। एन. रंगासामी 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। उप-राज्यपाल कैलाश नाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। रंगासामी के अलावा भाजपा के ए नमस्सिवायम और AINRC नेता मल्लादी कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली। नमस्सिवायम 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पिछली पुडुचेरी सरकार में वे गृह मंत्री थे। 4 मई को आए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुए। AINRC ने 16 में से 12 सीटें जीतकर 75% का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल किया। भाजपा ने 10 में 4 सीटें जीतकर 40% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत सकी और उसका स्ट्राइक रेट मात्र 6% रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के संस्थापक एन. रंगासामी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी है और केंद्र शासित प्रदेश के विकास पथ को मजबूत किया है। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया। इसमें लिखा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर थिरु एन. रंगासामी जी को हार्दिक बधाई। उन्होंने एक अनुभवी और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और पुडुचेरी के विकास को मजबूती दी है। जनता के कल्याण के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।

तमिलनाडु में टीवीके सरकार ने हासिल किया बहुमत

117 मतों की जरूरत,मिले 144 मत,इनमें 27 एआईएडीएम के सदस्यों का भी समर्थन

चेन्नई,13 मई 2026। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विजय को अपना बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें सदन में 144 विधानसभा सदस्यों का समर्थन मिला। सरकार के पक्ष में एआईएडीएम के 27 सदस्यों ने भी मतदान किया। तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल के बीच बुधवार सुबह 9:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। तमिलगा वेत्रि कड़गम पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। पहली बार राज्य में चुनाव लड़ने वाली टीवीके ने राज्य में सरकार बनाई है। आज टीवीके सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू की। इसके बाद टीवीके की सरकार के विश्वास मत के लिए मतदान कराया गया। तमिलनाडु की टीवीके सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विश्वास मत के दौरान सरकार को 144 सदस्यों का समर्थन मिला और बहुमत हासिल कर लिया है। टीवीके सरकार के पक्ष में पार्टी के 106 के अतिरिक्त कांग्रेस के 5,विदुथलाई चिरुथैगल काची के 2,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 विधायकों ने भी मतदान किया। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक कामराज ने भी सरकार को समर्थन दिया। इसके अलावा एआईएडीएमके के 27 सदस्यों ने भी सरकार के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार मुख्यमंत्री विजय ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है।

हिंदू धर्म जीवनशैली का हिस्सा,आस्था साबित करने के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,13 मई 2026। सबरीमला मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म एक जीवनशैली है और यह आवश्यक नहीं है कि हिंदू धर्म में बने रहने के लिए मंदिर जाना या धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, लोग अपनी झोपड़ी में दीपक जलाते हैं, बस इतना ही काफी है। न्यायालय ने हिंदू धर्म की सादगी और समावेशिता पर बल दिया। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा सहित विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि वेदों को स्वीकार करने के बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा और न ही किसी ने ऐसा कहा। मैं वेदों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या यह सच है कि आज जो लोग हिंदू कहलाते हैं, वे सभी वेदों को आध्यात्मिक और दार्शनिक सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार मानते हैं?

विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह....

भवानीपुर से विधायक बने सीएम शुभेंदु,नंदीग्राम सीट छोड़ी

नई दिल्ली,13 मई 2026। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार को ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नवनिर्वाचित विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और विधायकों को औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। प्रोटेम स्पीकर तापस राय की मौजूदगी में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से विजयी हुए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ ली।

भवानीपुर से विधायक बने नंदीग्राम सीट छोड़ने का निर्णय

शपथ ग्रहण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहने का निर्णय लिया है, जबकि नंदीग्राम सीट को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। विधानसभा परिसर में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली।

2021 से 2026 तक का राजनीतिक घटनाक्रम

2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जहां तत्कालीन विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित किया था। बाद में भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर विधानसभा में वापसी की थी। 2026 के चुनाव में एक बार फिर नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें राजनीतिक रूप से केंद्र में रहीं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत दर्ज की।

राजनीतिक संदेश और प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि भवानीपुर और नंदीग्राम से जुड़े इस राजनीतिक घटनाक्रम का असर आने वाले समय में राज्य की सत्ता संतुलन और रणनीतिक दिशा पर देखने को मिलेगा। यह निर्णय आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।

समारोह के दौरान विधायकों की उपस्थिति में औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं और सदन का माहौल पूरी तरह राजनीतिक उत्साह से भरा रहा।

दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार कार और लॉरी में भीषण भिड़ंत छह लोगों की मौत

चेन्नई,13 मई 2026। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के वेल्लाकोविल के पास बुधवार तड़के करूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार की लॉरी से टक्कर हो गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना वेल्लाकोविल में करूर राष्ट्रीय राजमार्ग पुलिस चौकी के पास तब हुई जब अधिकारी सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकराई एक लॉरी को हटाने में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस कांस्टेबल रविचंद्रन लॉरी चालक के साथ मिलकर वाहन को हटाने में मदद कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि उसी सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और खड़ी लॉरी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भीषण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कांस्टेबल रविचंद्रन, लॉरी चालक और कार में सवार चार लोगों सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पीएम मोदी ने पेश की मिसाल...

अपने काफिले का आकार घटाया संसाधन बचत का दिया बड़ा संदेश

नई दिल्ली,13 मई 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सादगी, प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के संतुलित उपयोग का संदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने अपने हालिया घरेलू दौरों के दौरान काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी है। खास बात यह रही कि इस बदलाव में सुरक्षा मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक, वडोदरा और गुवाहाटी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले में पहले की तुलना में कम वाहन शामिल किए गए। हालांकि,एसपीजी के सभी जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहे। सुरक्षा से जुड़े आवश्यक वाहन यथावत रखे गए, जबकि गैरजरूरी गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी गई।

खुद उदाहरण पेश कर दिया बड़ा संदेश : यह फैसला हैदराबाद में प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद सामने आया। इसे प्रशासनिक दक्षता, ट्रैफिक प्रबंधन और आम लोगों की सुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद काफिला छोटा कर ईंधन बचत और सादगी का संदेश देने की कोशिश की है।

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:13 AM Page 2

संपादकीय

लीक नहीं ठीक

हमारे तंत्र की नाकामी और परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचारियों की बढ़ती सेंध का ही नतीजा है कि पेपर लीक के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए तीन मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब पौने तेईस लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये परीक्षाएं देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5400 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। दरअसल,पेपर लीक होने के आरोपों के बाद जांच एजेंसियों की सिफारिश पर परीक्षा रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कथित रूप से डेटा लीक और धांधली की व्यापक जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि व्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए फिर से परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि एनटीए ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा निष्कर्षों की प्रारंभिक जांच के आधार पर परीक्षा स्थगन का फैसला लिया। निस्संदेह, इस फैसले ने उन लाखों छात्रों को निराश ही किया है जो महीनों से परीक्षा की तैयारी में लगे थे। अब उन्हें नये सिरे से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने एनटीए व केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कहा जा रहा है कि एनटीए में सुधार नहीं,अब पूरी संरचना बदलने की जरूरत है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि एनटीए के बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है। राजनेता पीपर लीक व प्रश्नपत्रों में गलती सामने आने को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने की मांग की जा रही है। साथ ही एनटीए के उद्देश्य और कार्यक्षमता को लेकर शंका जतायी जा रही है।

वहीं कांग्रेस का आरोप है कि एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से पांच में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं। इनमें जेईई मेन्स 2025 उत्तर कुंजी के दोषपूर्ण होने पर प्रश्नपत्र में 12 प्रश्न वापस लेने पड़े थे। मांग है कि एनटीए को केंद्रीयकृत करने के बजाय संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। वहीं एनटीए कह रहा है कि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। यह भी कि एनटीए अपने संसाधनों का प्रयोग करके दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी की जवाबदेही स्वीकारी है। दरअसल, आरोप है कि नीट का पेपर 'क्वेश्चन बैंक' के जरिये लीक किया गया,जिसमें फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीन से ज्यादा सवाल थे। जिसमें आधे हूबहू परीक्षा में आए। आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिये ये प्रश्नपत्र लाखों तक पहुंचे। हालांकि,इस मामले का खुलासा सीकर से हुआ,लेकिन कहते हैं कि पेपर पहले केरल से एक मई को आया और उसके तार नासिक से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े थे। एनटीए ने कहा है कि सात मई की रात एक व्हिसलब्लोअर से उन्हें पेपर लीक की सूचना मिली। बताते हैं कि सीकर के एक पीजी संचालक ने पेपर लीक की सूचना पुलिस को दी। कालांतर में पेपर से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल हो गई।

एनटीए द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के बाद एक दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। यह विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार के बाजार में लाखों छात्रों की मेहनत और सपने नीलाम हो रहे हैं। कुछ लोग लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगा रहे हैं। तभी कई बार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बावजूद किसी को बड़ी सजा अब तक नहीं मिली है। यही वजह कि नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की मांग की जा रही है क्योकि पेन-पेपर मोड में पेपर लीक होने की ज्यादा आशंका रहती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा को सुरक्षित व पारदर्शी बताया जा रहा है। साथ ही पारदर्शी जांच व जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। सवाल स्टाफ की आउटसोर्सिंग को लेकर भी उठे हैं। परीक्षाएं हाइब्रिड परीक्षा मॉडल के साथ ऑनलाइन कराने की भी मांग है।

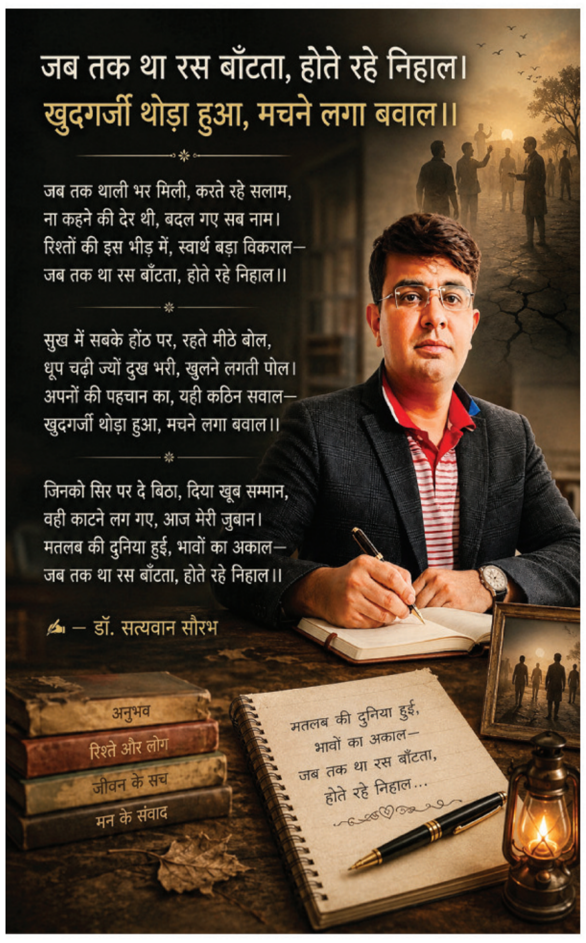

जनगणना कर्मी से कुछ नहीं छुपाएं,वरना हो सकता है जेल-जुर्माना

जनगणना का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। सरकार को सही आंकड़े चाहिए और नागरिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगी। यही कारण है कि जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को गोपनीयता के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। जनगणना में एकत्र की गई सूचनाएं व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील मानी जाती हैं। किसी भी प्रगणक द्वारा इन तथ्यों को बाहर साझा करना कानून के दायरे में गंभीर लापरवाही माना जाता है। यदि यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी ने जानकारी लीक की,तो उसके खिलाफ दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। इस बार स्वगणना को लेकर भी विशेष चर्चा बनी हुई है।

अजय कुमार,
लखनऊ (उ. प्र.)

2011 के बाद देश की आबादी में कितना इजाफा हुआ है, इसका पता लगाने के लिये जनगणना कर्मी 22 मई से लोगों के घर पहुंचना शुरू कर देंगे। आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना है। इससे पहले 1951, 1961,1971,1981,1991,2001, 2011 में भी जनगणना का कार्य हो चुका है। 2021 में कोरोना महामारी के चलते जनगणना का काम नहीं हो पाया था, जो अब 2026 में सम्पन्न होने जा रहा है। जनगणना के लिये सरकार को काफी व्यय और व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये आम हिन्दुस्तानी भी बाध्य है कि वह जनगणना कर्मी को सही तथ्य और जानकारी प्रदान करें। यदि जनगणना के दौरान कोई पुरुष/महिला किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाता/छिपाती है,तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। मतलब जनगणना कर्मी से कुछ भी छिपाना अब हल्की बात नहीं मानी जाएगी। जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, कोई तथ्य छिपाता है या जनगणना से जुड़े दायित्व का पालन नहीं करता,तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, यह प्रावधान केवल उत्तरदाता पर ही नहीं, बल्कि प्रगणक पर भी समान रूप से लागू होता है। यदि प्रगणक अपने काम के दौरान मिली जानकारी को बाहर किसी से साझा करता है, तो आरोप साबित होने की स्थिति में उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।

जनगणना से जुड़ी इस कानूनी व्यवस्था को लेकर इन दिनों प्रगणक और पर्यवेक्षक भी खासे सतर्क हो गए हैं। स्वगणना के दौरान कुछ लोगों द्वारा जानकारी छिपाने या अधूरी जानकारी देने की चर्चाओं ने जनगणना से जुड़े अमले को और अधिक सावधान कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि जनगणना केवल औपचारिक आंकड़ा जुटाने की प्रक्रिया नहीं है,बल्कि इसके आधार पर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, संसाधन तय करती हैं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करती हैं। ऐसे में अगर किसी स्तर पर जानकारी गलत दर्ज होती है या जानबूझकर छिपाई जाती है,तो उसका असर पूरी व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रगणकों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे घर-घर जाकर दर्ज की जाने वाली सूचनाओं को पूरी गंभीरता से सत्यापित करें। खासकर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारी सीधे प्रगणक पर आ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर यह माना जा रहा है कि यदि किसी ब्लॉक में परिवारों की संख्या, लोगों की संख्या या अन्य बुनियादी विवरण असामान्य रूप से कम पाए जाते हैं, तो यह संदेह का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण कराया जा सकता है,ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। स्वगणना में लोग स्वयं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ तथ्य छिपा देता है, तो इसका असर अंतिम आंकड़ों पर पड़ता है। कुछ मामलों में लोग आय, शिक्षा, परिवार के सदस्यों की संख्या, निवास की स्थिति या अन्य सामाजिक जानकारी को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसी हरकतें भले ही व्यक्तिगत स्तर पर छोटी लगें, लेकिन जब यह हजारों-लाखों घरों में होती हैं,तो राष्ट्रीय आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

इसी वजह से प्रगणकों को यह भी कहा जा रहा है कि वे केवल फॉर्म भरवाने तक सीमित न रहें,बल्कि जानकारी की संगति भी देखें। अगर किसी घर में लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है,जबकि आसपास की परिस्थिति कुछ और संकेत देती है,तो उसे तुरंत चिह्नित किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी घर में रहने वाले लोग बाहर चले गए हों,या किसी सदस्य का नाम जानबूझकर दर्ज न कराया गया हो। ऐसे मामलों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपनाकर वास्तविक तथ्य जुटाए जा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि संदेह के आधार पर जांच कराना जनगणना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के स्तर पर यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि यही जनगणना की प्राथमिक इकाई मानी जाती है। इसी स्तर पर मकानों, परिवारों और निवासियों का प्रारंभिक रिकॉर्ड तैयार होता है। यदि यही रिकॉर्ड गलत या अधूरा हो गया,तो आगे के सभी आंकड़ों में त्रुटि आ सकती है। इसलिए प्रगणकों को साफ निर्देश हैं कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। यदि किसी ब्लॉक में ज्यादा अनियमितता मिलती है,तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे न केवल संबंधित प्रगणक की भूमिका सवालों के घेरे में आएगी,बल्कि पर्यवेक्षण व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि जनगणना के काम में सतर्कता सिर्फ नियमों की वजह से नहीं,बल्कि सार्वजनिक हित की वजह से भी जरूरी है। देश की योजनाएं,विकास कार्य,स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोजगार से जुड़े आकलन और कई तरह के संसाधन वितरण जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या कम दिखाई जाती है,तो वहां मिलने वाले संसाधनों पर असर पड़ सकता है। इसी तरह यदि किसी समुदाय,बस्ती या इलाके की सही गिनती नहीं हुई, तो वे लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जनगणना अमले को यह समझाया जा रहा है कि हर विवरण की अहमियत है। एक गलत प्रविष्टि भी पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि प्रगणक,पर्यवेक्षक और संबंधित अधिकारी अब अधिक चौकन्ने हो गए हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जनता भी सहयोग करें और सही जानकारी दे। जनगणना को लेकर किसी तरह की अफवाह,डर या लापरवाही से बचना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना केवल सरकारी दस्तावेज नहीं,बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता का आईना है। इसमें जितनी सच्चाई होगी,नीति निर्माण उतना ही मजबूत होगा। अगर लोग अपनी जानकारी छिपाते हैं,तो वे सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं करते,बल्कि अपने इलाके और समुदाय के हिस्से के अधिकारों को भी कमजोर कर सकते हैं। इसी तरह यदि जनगणना कर्मी गोपनीयता भंग करते हैं,तो वे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रशासन अब यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि हर स्तर पर निगरानी सख्त रहे। प्रगणकों को बार-बार निर्देश दिए जा रहे हैं पर्यवेक्षक क्षेत्रीय जांच कर रहे हैं और जहां भी आंकड़ों में असामान्यता दिख रही है,वहां पुनर्परीक्षण की तैयारी है।

अधिकारियों की कोशिश है कि किसी भी तरह की कमी पहले ही पकड़ ली जाए, ताकि अंतिम आंकड़े अधिक सटीक और भरोसेमंद हों। जनगणना की सफलता इसी बात पर टिकी है कि न तो कोई तथ्य छूटे, न कोई गलत दर्ज हो और न ही कोई संवेदनशील जानकारी बाहर जाए।

सामाजिक हित और हम,इसे निभाने में कोताही क्यों?

विषम स्थितियों में आमजन का पहला काम सामूहिक-हित

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की सामाजिक चेतना और भागीदारी में निहित होती है। जब कोई राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक,ऊर्जा अथवा सामरिक विषमताओं से गुजरता है,तब केवल सरकार या सेना ही नहीं,बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक उस चुनौती का हिस्सा बन जाता है। इतिहास सदैव गवाह है कि जिन देशों के नागरिकों ने कठिन समय में संयम,अनुशासन और त्याग का परिचय दिया,वे राष्ट्र अधिक मजबूत होकर उभरे। राष्ट्र केवल सीमाओं,संसदों और संस्थाओं से नहीं बनता,बल्कि करोड़ों नागरिकों की चेतना, जिम्मेदारी और व्यवहार से निर्मित होता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों के समय देश के हित को सबसे ऊपर रखना प्रत्येक नागरिक का पहला दायित्व बन जाता है। भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि हर नागरिक को यह अनुभव होना चाहिए कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। आज विश्व अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रहा है। कहीं युद्ध की विभीषिका है,कहीं ऊर्जा संकट,कहीं महंगाई और आर्थिक अस्थिरता। विश्व की अनेक घटनाओं का प्रभाव भारत जैसे विशाल विकासशील देश पर भी पड़ता है। ऐसे समय में यदि देश का मुखिया जनता से ऊर्जा बचाने,आवश्यक वस्तुओं के विवेकपूर्ण उपयोग या आर्थिक संयम का आह्वान करते हैं,तो उसे केवल सरकारी निर्देश मानकर नहीं,बल्कि अपना स्वयं का काम समझकर स्वीकार करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को नहीं। यह कथन आज के उपभोक्तावादी दौर में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आवश्यकता और अंधाधुंध उपभोग के बीच का अंतर समझना ही सच्ची राष्ट्रसेवा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना था कि आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी नीतियों से नहीं आती,बल्कि उपभोक्ताओं और नागरिकों के व्यवहार से भी निर्मित होती है। यदि जनता विवेकपूर्ण आचरण करे तो बड़े आर्थिक संकटों का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऊर्जा संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि देश ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर हो और विश्व की परिस्थितियों के कारण तेल एवं गैस की कीमतें बढ़ जाएँ, तो उसका सीधा प्रभाव देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसे समय में यदि नागरिक बिजली, ईंधन और संसाधनों का संयमित उपयोग करें,सार्वजनिक परिवहन अपनाएँ, अनावश्यक उपभोग कम करें,तो यह समाज की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने वाला कदम बन जाता है। छोटी-छोटी सावधानियाँ भी बड़े परिणाम देती हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कहा करते थे किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का राष्ट्र बनाना है,तो उसमें तीन लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – माता,पिता और शिक्षक। इस कथन का व्यापक अर्थ यह है कि राष्ट्रनिर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं,बल्कि समाज के हर वर्ग की नैतिक भागीदारी से संभव होता है। आर्थिक संकट के समय समझदारी से खरीदारी करना भी देश हित का हिस्सा है।

आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह, कालाबाजारी को बढ़ावा देना,अफवाहों में आकर जरूरत से अधिक खरीदारी करना,यह सब देश की व्यवस्था को कमजोर करता है। कोविड महामारी के समय हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने दवाइयों, ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री का अनावश्यक भंडारण किया,जबकि अनेक नागरिकों ने सेवा, सहयोग और संयम का परिचय देकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की थी। विषम परिस्थिति यह तय करती है कि कि समाज स्वार्थ से चलेगा या संवेदनशीलता से। यहां यह बात समझ में आती है कि आर्थिक नीतियाँ तभी सफल होती हैं जब आमजन सहयोग की भावना से जुड़ें। सामरिक संकट के समय तो नागरिकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते,वे देश के भीतर अनुशासन,धैर्य और एकता से भी जीते जाते हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अनेक देशों के नागरिकों ने राशन व्यवस्था अपनाई,ईंधन की बचत की और राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत सुविधाओं का त्याग किया। भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाया। वह केवल आर्थिक आंदोलन नहीं था,बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक था। यह रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन, सामाजिक समरसता और निष्ठा से भी होती है।

आज सोशल मीडिया और त्वरित सूचना के युग में एक नई जिम्मेदारी भी नागरिकों के सामने है। संकट के समय अफवाहें फैलाना,भ्रामक सूचनाओं को साझा करना या समाज में भय और विभाजन पैदा करना भी देश के विरुद्ध कार्य है। जागरूक नागरिक वही है जो सही-सही जानकारी पर भरोसा करे और समाज में सकारात्मक सहयोग का वातावरण बनाए। वास्तव में राष्ट्रहित कोई कठोर नारा नहीं कोई भाषण या जुमलेबाजी नहीं बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान और व्यवहार है। सड़क पर नियम पालन करना,पानी और बिजली बचाना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना,स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना,सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और संकट के समय संयम रखना यही आधुनिक सामाजिक दायित्व के वास्तविक रूप हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि नागरिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। लोकतंत्र केवल सरकार से अपेक्षाएँ रखने का नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की भी व्यवस्था है।

यदि हर नागरिक यह सोच ले कि उसका छोटा-सा प्रयास भी देश को मजबूत बना सकता है, तो कोई भी आर्थिक,सामाजिक या सामरिक संकट भारत की प्रगति को रोक नहीं सकता। राष्ट्र वही सही बनता है, जहाँ नागरिक अपने निजी हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हित को महत्व देते हैं। समाज और देश के हित में किया गया छोटा-सा कार्य भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि का आधार बन जाता है। इसलिए सामाजिक विषम परिस्थितियों में सामाजिक हित निभाने में कोताही नहीं,बल्कि सजग सहभागिता ही सच्ची देश सेवा का प्रमाण है।

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

जितनी भी जिन्दगी कटी है सब तेरे नाम

जितनी भी ज़िन्दगी कटी है सब तेरे नाम
बुरा किया अच्छा किया है सब तेरा काम
जैसी बुद्धि दी तूने है उसी का परिणाम
अपने कर्मों का फल भुगतेगा क्यों बन रहा अनजान

जिंदगी में किससे मिलना है तुझे नहीं मालूम
किससे मिलाना है यह वही तय है करता
मालूम है तुझे कि जाना पड़ेगा एक दिन खाली हाथ
मोहमाया में फंस गया जाने से बहुत है डरता

बने बनाये खेल को बिगाड़ना
या बिगड़े हुए खेल को बनाना
किसी के हाथ में तो कुछ भी नहीं
अपनी मर्जी से आता है उसको नचाना

कभी करता है वह दिल्लगी
कभी उपहास है उड़ाता
भटकाता है अकेली राहों में
तो फिर राह भी है दिखाता

जिंदगी को जो यूं ही तमाम कर दिया
जिसने दिया सब कुछ उसी को बदनाम कर दिया
अवसर जो मिले आगे बढ़ने के उन्हें गंवा बैठा
दूसरों का जीना भी हराम कर दिया

संजय एम तराणेकर
इन्दौर
(मध्य प्रदेश)

राजनीति का आईना

सत्ता की गलियों में चलता,वक्त हैं बड़ा बलवान,
कल जिनके 'जयकारे' गूंजे,आज वही अनजान।
नेहरू की विरासत थी,जिस पर देश इतराता था,
इंदिरा का दृढ़ साहस, 'हिंदुस्तान' आगे जाता था।

यूं राजीव के सपनों ने भी,नई दिशा दिखलाई थी,
राजनीति की आँधी ने,हर 'तस्वीर' बदलवाई थी।
राहुल-प्रियंका नाम बड़े,जनता 'मन' पढ़ना होगा,
सिर्फ विरासत से नहीं, 'संघर्षों' में भी बढ़ना होगा।

मीडिया के मंचों पर चाहे, चेहरे क्यों चमकाए जाएँ,
जनता केवल कर्म देखती, वादें कब बहलाए जाएँ।
लोकतंत्र का यही उसूल है, 'जनमत' सबसे ऊपर है,
जो जनता के दर्द समझे, वही असली नेता सुपर है।

पर्यावरण असंतुलन विश्व की सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या

डॉ.राघवेंद्र शर्मा

पर्यावरण असंतुलन आज भारत ही नहीं,बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या बन चुका है। जिस विकास को हम अपनी प्रगति का पर्याय मान रहे हैं, वह कहीं न कहीं हमारी जीवनरेखा, प्रकृति को ही कमजोर कर रहा है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है। इसके दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन,अनियमित मौसम और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हमें न केवल तात्कालिक उपाय करने होंगे,बल्कि अपनी जीवनशैली और विकास की परिभाषा में भी मूलभूत परिवर्तन लाने होंगे। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा प्रकृति के संसाधनों का उपयोग किया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह उपयोग 'दोहन' की सीमा पार कर 'शोषण' बन गया है। सड़कें बनाने, उद्योग स्थापित करने और आवास योजनाएं लागू करने के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई निर्बाध रूप से जारी है। जंगल के जंगल साफ़ हो रहे हैं और कंक्रीट के जंगल उनका स्थान ले रहे हैं। विकास की यह दौड़ इस मूलभूत सत्य को अनदेखा कर रही है कि पेड़ केवल लकड़ी या जमीन घेरने वाले तत्त्व नहीं हैं,बल्कि वे पृथ्वी के फेफड़े हैं। वे हमें प्राणवायु (ऑक्सीजन) देते हैं,कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं,मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और जल चक्र को बनाए रखते हैं।

असफल पौधारोपण और परिणाम : समस्या केवल पेड़ों के काटने तक सीमित नहीं है,बल्कि उसके बाद की निष्क्रियता में भी है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं,उतने नए पेड़ लगा दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। जितने पेड़ काटे जाते हैं, उतने नए नहीं लगाए जाते और जो लगाए भी जाते हैं,उनमें से अधिकतम मर जाते हैं। पौधारोपण अभियानों में अक्सर केवल खानापूर्ति होती है।पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल,पानी देना या उन्हें जानवरों से बचाने का कार्य सही ढंग से नहीं होता। फलतः बहुत कम पौधारोपण सफल हो पाता है। यह स्थिति 'मृत पौधे' और 'कटे हुए पेड़' के बीच एक बड़ा असंतुलन पैदा करती है,जिसके फलस्वरूप पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। वायु में कार्बन का स्तर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और जैव विविधता खतरे में है। इस पर्यावरण असंतुलन का सीधा असर मानव जीवन और उसकी गुणवत्ता पर पड़ रहा है। तेजी से बढ़ते बड़े महानगरों में पेड़ों की छांव नसीब नहीं है। जहाँ कभी घने वृक्षों की शीतलता मिलती थी,वहाँ अब तपती कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें हैं, जो अतिरिक्त गर्मी के वातावरण को जन्म देती हैं। शहरों में शुद्ध हवा और ताज़गी का अभाव है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारियाँ और तनाव बढ़ रहे हैं। शहर के बीचों-बीच एक बड़े पेड़ का होना न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति और सौंदर्यबोध के लिए भी आवश्यक है।

अनियमित मौसम और इसके प्रभाव : पेड़ों की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण मौसम अनियमित हो रहे हैं। अत्यधिक गर्मी,अप्रत्याशित बारिश, लंबे समय तक सूखा, और अचानक बाढ़,ये सब जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत हैं। कहीं कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाती है,तो कहीं लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। यह अनियमितता कृषि को प्रभावित कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। मौसम की यह अनिश्चितता सीधे तौर पर मानव जीवन की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचा रही है।

समाधान की ओरः एक नया दृष्टिकोण : यह स्पष्ट है कि अब हमें एक अलग राह पर चलने की आवश्यकता है। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हम ऐसे विकल्प ढूंढ़े,जहाँ पेड़ काटे बगैर विकास संभव हो। निर्माण परियोजनाओं को इस तरह से नियोजित करना होगा कि वे यथा संभव कम से कम वृक्षों को प्रभावित करें। इसके लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों और 'ग्रीन आर्किटेक्चर' का उपयोग किया जा सकता है। शहरों के क्षैतिज विस्तार को नियंत्रित कर ऊर्ध्वाधर विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे कम भूमि का उपयोग हो और जंगल सुरक्षित रहें। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सौर,पवन, तथा जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना समय की आवश्यकता है,जिससे प्रदूषण कम हो और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षित रहे। समय की मांग यह भी है कि जब बड़े वृक्ष काटना मजबूरी हो (जैसे कि राष्ट्रीय हित की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए),तो उन्हें सीधे काटने के बजाय,उन्हें दूसरी जगह पुनःस्थापित किया जा सकता है। वृक्ष प्रत्यारोपण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

C M Y K

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:13 AM Page 3

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार भाजपा नेता की मौत

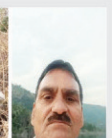

-संवाददाता-
विश्रामपुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के कुम्दा-विश्रामपुर मार्ग पर बुधवार की सुबह सड़क हादसे में शिवनंदनपुर निवासी भाजपा नेता एवं व्यवसायी कमलेश चौबे की मौत हो गई। जबकि घटना में एक अन्य युवक को भी गंभीर चोटें आई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे झाड़ियों के बीच फंस गई। इसके बाद चालक वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता को बिश्रामपुर अस्पताल भिजवाया। यहां से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत शिवनंदनपुर निवासी 60 वर्षीय कमलेश चौबे भाजपा नेता थे। वे किराना एवं पान मसाला व्यवसाय से भी जुड़े थे। बुधवार की सुबह वे अपने बाइक से व्यापारिक कार्य से कुम्दा-कसकेला क्षेत्र गए थे। काम पूरा कर वापस विश्रामपुर लौटने के दौरान कुम्दा मार्ग पर स्थित बाबा मस्तनाथ मंदिर से लगभग एक किलोमीटर आगे पीछे से आ रही स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 29 एजी 0413 के चालक ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे कमलेश चौबे सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर विश्रामपुर पुलिस एवं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्रामपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर पीएम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव लेकर उनके गृह ग्राम हासनदाग मेराल जिला गढ़वा झारखंड रवाना हो गए। स्व. कमलेश चौबे झारखंड भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय चौबे के भाई थे। वे अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र एवं एक पुत्री सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। दुर्घटना में व्यवसायी की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

उदयपुर सीएचसी में 10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन शुरू,अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति श्रीमती राधा रवि ने किया शुभारंभ...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन शुरू हुआ। पूर्व में निरीक्षण के दौरान उदयपुर क्षेत्र में कुपोषित बच्चों के बेहतर उपचार और देखभाल हेतु कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू करने आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देशित किया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर में 10 बिस्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र का जिला खनिज न्यास निधि मद से जीर्णोधार कार्य, मानव संसाधन की व्यवस्था, पोष्टिक आहार इत्यादि व्यवस्था की गई। आवश्यक कार्यवाही पश्चात 4 मई को अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति श्रीमती राधा रवि के द्वारा 10 बिस्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

कल्याणपुर जंगल में हथियारबंद बदमाशों की दस्तक,राहगीरों से लूट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग एक बार फिर दहशत के साये में नजर आने लगा है। मंगलवार देर रात कल्याणपुर जंगल में हथियारबंद युवकों द्वारा ऑटो चालक से मोबाइल लूट और कार सवारों को रोककर लूट की कोशिश की घटना ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है। लंबे समय बाद इस मार्ग पर हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों और रात में सफर करने वाले वाहन चालकों में भय का माहौल है। करीब दो दशक पहले अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग लूटपाट और राहजनी की घटनाओं के कारण बदनाम माना जाता था। जंगल और सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर बदमाश राहगीरों को निशाना बनाते थे। हालांकि पुलिस कार्रवाई और लगातार गश्त के कारण ऐसी घटनाएं लगभग बंद हो गई थीं, लेकिन मंगलवार रात हुई वारदात ने पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी ऑटो चालक धर्मेंद्र यादव मंगलवार रात करीब 12.40 बजे अंबिकापुर से लौट रहा था। इसी दौरान कल्याणपुर जंगल के पास 6 बाइक में सवार 11 से 12 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। बदमाशों के हाथ में पिस्टल थी और उन्होंने चालक को धमकाते हुए पैसे की मांग की। धर्मेंद्र ने बताया कि उसके पास नकदी नहीं थी। इस पर आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। हथियारबंद युवकों की संख्या अधिक होने के कारण वह विरोध नहीं कर सका। घटना के बाद वह किसी तरह वहां से निकला और पुलिस को सूचना दी। बदमाशों का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने उसी दौरान शादी समारोह से लौट रहे धरमपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल की कार को भी रोकने का प्रयास किया। जैसे ही कार की रफ्तार कम हुई, बदमाशों ने चालक की ओर पिस्टल तान दी। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और मौके से निकल गया। इसके बाद आरोपी बाइक से जंगल की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी, लटोरी चौकी प्रभारी अरुण कुमार गुप्ता और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रतापपुर एसडीओपी अनुप एक्का ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के इलाकों में संदिग्ध युवकों की तलाश कर रही है।

थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर मोबाइल लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है। बदमाश 6 बाइक में सवार थे और कुछ के पास हथियार भी थे। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रतापपुर मार्ग पर फिर से असामाजिक तत्व सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। यदि समय रहते सख्ती नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं।

पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड,अपराध दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ बीएनएस एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार महिला ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका विवाह वर्ष 2013 में ईद मोहम्मद से हुआ था। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और करीब दो महीने से तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 10 मई की सुबह जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर एआई तकनीक के माध्यम से बनाए गए अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए थे। जांच करने पर पता चला कि वीडियो उसके पति की इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड किया गया था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, सामाजिक रूप से बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की नीयत से यह कृत्य किया है। शाम तक वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य पीड़िता ने पुलिस को सौंप दिए हैं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 77, 79, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 ई और 67 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध और एआई तकनीक के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री सामने आने पर तत्काल शिकायत करने की अपील की है।

पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में श्रुति सोंधिया का शानदार प्रदर्शन

सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर की छात्रा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बढ़ाया गौरव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर की कक्षा 11वीं की छात्रा श्रुति सोंधिया ने आठवीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, परिवार और शहर का नाम गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता का आयोजन राजिम में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया था।नगर के मणिपुर, अंबिकापुर निवासी श्रुति सोंधिया, पिता प्रदीप सोंधिया ने 53 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेते हुए शानदार प्रदर्शन किया। श्रुति ने स्क्वाट में 30 किलो, बेंच प्रेस में 20 किलो तथा डेड लिफ्ट में 60 किलो वजन उठाकर कुल 110 किलो भार उठाने का रिकॉर्ड दर्ज किया। उनके इस प्रदर्शन को प्रतियोगिता में काफी सराहा गया।श्रुति की इस उपलब्धि से परिवार के सदस्यों, स्कूल प्रबंधन एवं सहपाठियों में खुशी का माहौल है। विद्यालय परिवार ने इसे छात्राओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में बेटियां लगातार नए मुकाम हासिल कर रही हैं।

पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर्स के साथ चलाएंगे जागरूकता अभियान,18 युवाओं का चयन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग और जनजागरुकता गतिविधियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 18 युवाओं का चयन किया है। चयनित अभ्यर्थी अब पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर जिलेभर में जागरुकता कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पुलिस विभाग द्वारा इसके लिए विशेष चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के बाद अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इस दौरान संवाद क्षमता, सामाजिक जागरुकता, नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक सहभागिता और जनहित कार्यों के प्रति रुचि के आधार पर मूल्यांकन किया गया। चयन प्रक्रिया में भार्गवी द्विवेदी ने प्रथम, आस्था गुप्ता ने द्वितीय और डिंपल चौधरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अन्य चयनित अभ्यर्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए समाज सेवा के प्रति सकारात्मक सोच दिखाई।

देंगे निः शुल्क सेवाएं : चयनित स्वयंसेवक सरगुजा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा, यातायात नियमों, नशा मुक्ति अभियान और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में निः शुल्क सेवाएं देंगे। इनका मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा समाज में जागरूकता बढ़ाना रहेगा।

2022 से चल रहा अभियान : सरगुजा पुलिस वर्ष 2022 से सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर्स द्वारा स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इन अभियानों का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है।

अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई चयन प्रक्रिया : चयन और साक्षात्कार प्रक्रिया नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इसमें अनुज जायसवाल, अमन पुरी, व्याख्याता संजय गुप्ता तथा महिला थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

लखनपुर के पोड़ी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप हर द्वार तक पहुँच रहा प्रशासन : विधायक प्रबोध मिंज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत आज सरगुजा जिले के विकासखंड लखनपुर के ग्राम पोड़ी में 'जन समस्या निवारण शिविर' का आयोजन किया गया। 'संवाद से समाधान तक' की थीम पर आधारित इस शिविर में 18 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित किया गया है।

विधायक ने शिविर स्टॉल का किया निरीक्षण : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने शिविर में लगाए गए 34 विभागीय स्टालों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि प्रशासन स्वयं गांव-गांव और द्वार-द्वार पहुँचकर जनता की समस्याओं का निराकरण करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का विभागवार समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कर संबंधित हितग्राहियों को सूचित किया जाए। श्री मिंज ने जोर देकर कहा कि 'विष्णु की सरकार में हर गारंटी पूरी हो रही है और सुदूर अंचलों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है। अब पहुंच विहिन गांवों में सड़कों का जाल बीछ रहा है। सुशासन के संकल्प के साथ गांव के अंतिम व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले सुनिश्चित किया जा रहा है। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना और शासन की जनहितैषी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना रहा।

शिविर में हितग्राही मूलक योजनाओं का मिला लाभ : शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 164 हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सामग्री एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5 नवीन राशन कार्ड, 5 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति तथा 13 जॉब कार्ड वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 आयुष्मान कार्ड, 35 हितग्राहियों को चश्मा वितरण किया गया। शिक्षा विभाग ने 59 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए। कृषि विभाग द्वारा 9 किसानों को केसीसी कार्ड एवं 11 हितग्राहियों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। वहीं राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजनांतर्गत 22 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख पट्टा प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मोनिका पैकरा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह, जनपद सदस्य श्री सुदर्शन सिंह, श्री प्रभाकर खलको, श्रीमती गणेश्वरी राजवाड़े सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचगण उपस्थित रहे। प्रशासनिक अमले में एसडीएम श्री राम राज सिंह, जनपद सीईओ श्री प्रकाश सिंह सहित सभी विभागों के जिला एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मातृत्व दिवस पर बुजुर्ग माताओं का सम्मान

वसुधा सदस्यों ने चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद, गीत-भजन से भावुक हुआ माहौल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

मातृत्व दिवस के अवसर पर अलंकार पंचशील में रविवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की बुजुर्ग माताओं का सम्मान किया गया तथा वसुधा परिवार की महिलाओं ने उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। आयोजन में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी संस्था से विद्या दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने मां को सृष्टि का आधार बताते हुए मातृत्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही छोटी-छोटी प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से मां की शक्ति और त्याग को समझाया। उनके विचारों से उपस्थित महिलाएं भावुक हो गई। ब्रह्मकुमारी संस्था की बहन रेखा ने 'तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ओ मां...' गीत की मधुर प्रस्तुति दी। गीत सुनकर कई महिलाएं अपनी मां को याद कर भावुक हो उठीं। इस अवसर पर डॉ. पुष्पा सोनी, डॉ. मंजू शर्मा, संतोष पांडे, मुखरानी सिंह, श्यामा स्वर्णकार, प्रभा मुंजे और जया तिवारी ने भी मां के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बुजुर्ग माताओं द्वारा भजन और गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन संयोजिका वंदना दत्ता ने किया। आयोजन में चंदा शुक्ला, शारदा अग्रवाल, प्रभा तिवारी, प्रेमलता सिंह, लीलावती पांडे, राजकुमारी शुक्ला, विमला देवी पाठक, रामरती देवी अग्रवाल, चमेली अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में जयश्री स्वर्णकार, अनुभा डबराल, च्यति अग्रवाल, जानकी सिंह, बलविंदर टूटेजा, नमिता चावला, मिलन शर्मा, रीता अग्रवाल, नीलू गुप्ता, सवित सिंह, संजीता स्वर्णकार, शुभा गुप्ता, मंजू जायसवाल, डॉ. मीरा शुक्ला, शशि श्रीवास्तव, मधु शुक्ला सहित अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

आंधी-तूफान के बाद गाज गिरने से 14 मवेशियों की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को आंधी-तूफान और गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 14 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं एक बछिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका पशु चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है।

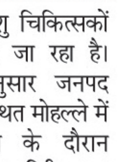

जानकारी के अनुसार जनपद कार्यालय के पीछे स्थित मोहल्ले में तेज आंधी-तूफान के दौरान अचानक आकाशीय गिरी। उस समय बड़ी संख्या में मवेशी एक स्थान पर मौजूद थे। बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही 14 मवेशियों की मौत हो गई। घायल बछिया का पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है।

तेज रफ्तार कार का कहर...6 बाइक व एक कार को मारी टक्कर,कार सवार 2 युवक हिरासत में

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मंगलवार की रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड स्थित सद्भावना चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर 6 बाइक और एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

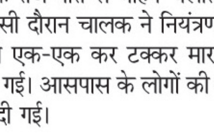

बताया जा रहा है कि कार चालक तेज गति से वाहन चलाते हुए ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को एक-एक कर टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

निधन

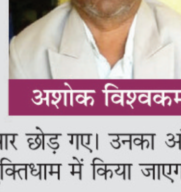

अशोक विश्वकर्मा

शहर के कंपनी बाजार निवासी व्याख्याता शिक्षक अशोक कुमार विश्वकर्मा पिता स्व. अमरदयाल विश्वकर्मा का 56 वर्ष की आयु में हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया। वे अपने पीछे दो पुत्र राज विश्वकर्मा, युवराज विश्वकर्मा सहित भरापूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार 14 मई को शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा।

जिले में मिली दुर्लभ पांडुलिपियां,चौबे परिवार ने सहेजकर रखी थी पूर्वजों की धरोहर

कलेक्टर श्री अजीत वसंत की मौजूदगी में पांडुलिपियों का हुआ डिजिटल संरक्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 13 मई 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर एवं ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के जिला समिति के अध्यक्ष श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत सीईओ एवं समिति के सदस्य सचिव श्री विनय अग्रवाल के निर्देशन में जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' अभियान जारी है। जिसके अंतर्गत जिले में प्राचीन एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है। अभियान के तहत जिले में विभिन्न ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों का संग्रहण कर उन्हें ज्ञानभारतम् पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। इसी कड़ी में दरिमा तहसील के बरगंवा ग्राम में दो दुर्लभ पांडुलिपियां प्राप्त हुईं।

पीढ़ियों से चौबे परिवार ने सहेजकर रखी थी पूर्वजों की यह धरोहर- पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के दौरान दरिमा तहसील के बरगंवा ग्राम में 72 वर्षीय श्री बाल कृष्ण चौबे के घर पांडुलिपियां मिली। उन्होंने पांडुलिपियों को अपने पूजाघर में बस्ते में बांधकर रखा था। पांडुलिपियों के दो बंडल में एक बंडल बन दुर्गा महामंत्र और दूसरा दुर्गा सप्तशती का था। उन्होंने बताया कि बन दुर्गा महामंत्र पांडुलिपी उनके छोटे दादा स्वर्गीय श्री देवदत्त शर्मा ने स्याही का प्रयोग कर 27 अगस्त 1932 में हाथ से लिखा था, यह छोटे पुस्तकनुमा आकार में है। वहीं दूसरा 183 पन्नों का दुर्गा सप्तशती पांडुलिपि लगभग वर्ष 1895-1896 में लिखा गया ही, जिसको लिखने वाले पूर्वज की जानकारी नहीं हैं।

CMYK

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:13 AM Page 4

कुदरगढ़ धाम से निकला सौहार्द का संदेश,कलेक्टर रेना जमील की एक तस्वीर बनी सामाजिक समरसता की मिसाल

जब धर्म जोड़ने का माध्यम बने,तब समाज मजबूत होता है...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम से सामने आई एक तस्वीर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, यह केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम की तस्वीर नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने वाला ऐसा संदेश है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। देश और समाज में अक्सर धर्म, जाति और पहचान को लेकर बहस और विवाद देखने को मिलते हैं, कई बार राजनीति भी इन्हीं मुद्दों के सहारे लोगों को बांटने की कोशिश करती दिखाई देती है, ऐसे माहौल में सूरजपुर जिले की कलेक्टर रेना जमील की यह तस्वीर लोगों के बीच एक अलग सोच और सकारात्मक संदेश लेकर आई है, तस्वीर में कलेक्टर रेना जमील माता के चित्र के सामने श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं, 'सोमनाथ स्वाभिमान' के जयघोष के बीच उनका यह भाव यह बताता है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता और एक-दूसरे के विश्वास के प्रति सम्मान में छिपी है।

धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

भारत को सदियों से अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है, यहां मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे के कीर्तन और चर्च की प्रार्थनाओं के बीच एक साझा संस्कृति विकसित हुई है, यही कारण है कि भारतीय समाज की असली ताकत उसकी एकता और सहिष्णुता मानी जाती है, कुदरगढ़ धाम में दिखाई दिया यह दृश्य इसी परंपरा को जीवंत करता नजर आया, मुस्लिम समुदाय से आने वाली एक महिला अधिकारी का मंदिर परिसर में श्रद्धा व्यक्त करना यह दर्शाता है कि इंसानियत और सम्मान किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधे नहीं होते, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तस्वीर उन लोगों के लिए भी जवाब है जो समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों ने इसे 'सद्भाव और सम्मान की तस्वीर' बताया है।

जमीन से जुड़ी अधिकारी की बन रही पहचान

कलेक्टर रेना जमील की चर्चा केवल इस तस्वीर तक सीमित नहीं है, जिले में उनकी कार्यशैली को लेकर भी आम लोगों के बीच सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है, ग्रामीणों और नागरिकों का कहना है कि वे आम जनता से सीधे संवाद करने वाली अधिकारी के रूप में पहचान बना रही हैं, लोग बताते हैं कि कई बार प्रशासनिक दफ्तरों में आम आदमी खुद को असहज महसूस करता है, लेकिन सूरजपुर में स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है, यहां लोग यह महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन केवल आदेश देने तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का भी प्रयास कर रहा है, कई स्थानीय लोगों का कहना है कि कलेक्टर रेना जमील बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों से मिलती हैं और यही कारण है कि उनकी छवि एक संवेदनशील और जमीन से जुड़ी अधिकारी की बन रही है।

समाज को क्या सीख देती है यह तस्वीर?

यह तस्वीर केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी देती है—कि किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, शांति और मानवता है, जब एक प्रशासनिक अधिकारी समाज के हर वर्ग और हर परंपरा का सम्मान करते हुए दिखाई देती हैं, तब यह संदेश और मजबूत होता है कि विकास और सामाजिक समरसता साथ-साथ चल सकते हैं, आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी बातों को लेकर नफरत फैलाने की कोशिशें होती हैं, वहीं कुदरगढ़ धाम से सामने आई यह तस्वीर लोगों को यह याद दिलाती है कि भारत की पहचान उसकी 'एकता में अनेकता' है।

सौहार्द की तस्वीर बनी चर्चा का विषय

कुदरगढ़ धाम से सामने आई यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की जा रही है, लोग इसे 'धर्म से ऊपर इंसानियत' और 'भारतीय संस्कृति की असली तस्वीर' जैसे शब्दों के साथ साझा कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि यदि समाज में इसी तरह एक-दूसरे की आस्था का सम्मान करने की भावना मजबूत हो, तो नफरत और विभाजन की राजनीति अपने आप कमजोर पड़ जाएगी, सूरजपुर से निकली यह तस्वीर आज केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को यह संदेश देती नजर आ रही है कि धर्म का सबसे सुंदर रूप वही है, जो इंसानों को जोड़ता है, सम्मान सिखाता है और प्रेम का रास्ता दिखाता है।

पत्रकार वार्ता के दौरान सूरजपुर कलेक्टर का अलग ही अंदाज आया नजर,संवाद ही समाधान और सुशासन का जरिया के तर्ज पर जिले को मिलेगी नई पहचान

कलेक्टर सुरजपुर ने जिले में अपने आगमन के तत्काल पश्चात पत्रकार वार्ता आयोजित की, पत्रकार वार्ता में नव पदस्थ सुरजपुर कलेक्टर का अंदाज अन्य पूर्व कलेक्टरों से अलग ही नजर आया, उन्होंने संवाद को ही समाधान और सुशासन का जरिया बतलाया, जहां आज यह देखने को मिलता है कि संवाद से अधिकारी दूर भागने का प्रयास करते हैं कलेक्टर सुरजपुर ने इसे आवश्यक बतलाते हुए इसे प्रेरणा बतलाया, उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं तभी बेहतर ढंग से पूर्ण होंगी अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सकेगा जब संवाद बना रहेगा,उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई योजनाएं चला रही है उनकी प्राथमिकता है कि सभी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, सुरजपुर कलेक्टर का अंदाज कोरिया की पूर्व कलेक्टर से अलग भी कहा जा रहा है, जहां कोरिया कलेक्टर सीमित एक समूह के भीतर संवाद कायम रखकर कार्य करने की आदि थीं सूरजपुर कलेक्टर ने संवाद के जरिए सुशासन की बात कही है।

आजादी के 78 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव

सकरिया पंचायत के आश्रित गांव में 150 आदिवासी परिवार सड़क,पुल और आंगनबाड़ी के लिए तरस रहे

-मनोज कुमार-

लखनपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद विकास की किरण कई गांवों तक नहीं पहुंची है। जनपद पंचायत लखनपुर अंतर्गत सकरिया पंचायत में आने वाले बैंदो खोरा कापु टिकरा गांव जो लुड्रा विधानसभा में है यहां के करीब 150 आदिवासी परिवार आज भी सड़क, पुल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। बारिश के मौसम में स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाती है। नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को सामान लाने, इलाज कराने और अन्य जरूरी कामों के लिए नदी पार करनी पड़ती है। कई बार जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान रहते हैं। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र न होने के कारण छोटे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही गांव को भुला दिया जाता है। एक स्थानीय ग्रामीण ने बताया, 'हर चुनाव में सड़क-पुल बनाने का वादा किया जाता है। नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। हम आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बच्चों और बीमारों की हालत सबसे खराब है।' जिले के कई अन्य गांवों की तरह बैंदो खोरा कापु टिकरा भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। ग्रामीण अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, ताकि सड़क, पुल और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा सके।

लंबे समय से फरार चल रहे कोयला तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

-संवाददाता-

बलरामपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र रात्रि गस्त के दौरान पुलिस ने लावारिस हालत मे ट्रेलर वाहन कोयला जप्त किया था, वाहन स्वामी और चालक की तलाश में जुटी थी, पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। जानकारी के अनुसार दिनांक 22/03/2026 को थाना चलगली स्टाफ को रात्रि गस्त पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम डोंगरो में रात्रि 22.30 बजे ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 AL 4354 में कोयला लोड लावारिस हालत में सड़क किनारे पाये जाने पर थाना चलगली पुलिस द्वारा ट्रेलर वाहन को जप्त कर माल एवं मालिक का पतासाजी के दौरान ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 AL 4354 का चालक के द्वारा कोयले का कागजात पेश करने पर उक्त दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया बोगस/कुटरचित होना पाया गया। तत्संबंध में थाना चलगली में अप.क 23/2026 धारा 318, 338, 336, 3 (5) भान्यासं के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अरोपी संदेही सीताराम पिता प्रेमलाल उम्र 38 साल जाति गोड़ सा. बसेराकलॉ से पूछताछ करने पर बताया कि, ट्रांसपोटर आफताब खॉन से लगभग 32 टन कोयला मंगाया था।

दैनिक घटती-घटना की खबर का असर : मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँची 'पोस्टिंग दरबार' की गूंज.....

विधायक के मंच पर अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर RTI एक्टिविस्ट ने की शिकायत,कलेक्टर सूरजपुर को जांच के निर्देश

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)। दैनिक घटती-घटना में प्रकाशित बहुचर्चित खबर 'जन्मदिन या पोस्टिंग दरबार?' अब बड़ा प्रशासनिक मामला बनती नजर आ रही है, विधायक के जन्मदिन कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित सक्रिय मौजूदगी को लेकर उठे सवाल अब सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर सूरजपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

क्या था पूरा मामला?

दैनिक घटती-घटना ने अपने विशेष समाचार में विधायक के जन्मदिन कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे, खबर में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि क्या सरकारी अधिकारी अब राजनीतिक आयोजनों में केवल 'शुभकामना' देने जाते हैं या फिर यह 'पोस्टिंग और नेटवर्किंग' का नया मंच बनता जा रहा है? समाचार में मंच पर मौजूद कुछ अधिकारियों की भूमिका, गीत-संगीत कार्यक्रम में सहभागिता और कथित चरण स्पर्श जैसे दृश्य भी चर्चा का विषय बने थे।

अब मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँची शिकायत

आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी सहित कुछ अधिकारी-कर्मचारी राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल दिखाई दिए, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों की भावना के विपरीत है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि कई विभागीय शिकायतें लंबित होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की राजनीतिक आयोजनों में सक्रियता प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है।

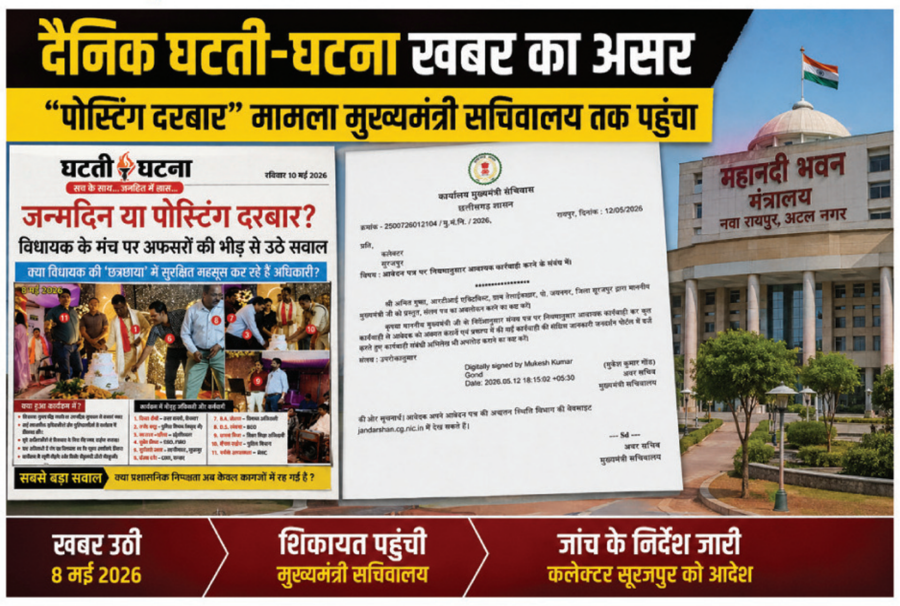

मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिया संज्ञान

10 मई को खबर प्रकाशित हुई और 12 मई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी पत्र में कलेक्टर सूरजपुर को निर्देशित किया गया है कि शिकायत पत्र और संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, सचिवालय ने यह भी कहा है कि की गई कार्रवाई की जानकारी जनदर्शन पोर्टल पर दर्ज की जाए और संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएं, यानी अब यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक फाइलों तक पहुँच चुका है।

'जन्मदिन या पोस्टिंग दरबार?' शीर्षक ने खड़े किए थे कई सवाल

दैनिक घटती-घटना की खबर ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी थी, खबर में सवाल उठाया गया था कि क्या अधिकारी राजनीतिक संरक्षण की तलाश में ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं? क्या सरकारी पद की गरिमा धीरे-धीरे राजनीतिक मंचों के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या यह प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए खतरे का संकेत है? इन सवालों को लेकर जिलेभर में चर्चा तेज हो गई थी।

सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हुई थी खबर

खबर प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया में भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं, कुछ लोगों ने इसे 'प्रोटोकॉल से बाहर की सक्रियता' बताया, तो कुछ ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक निकटता से बचना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना अलग बात है, लेकिन मंचीय सक्रियता प्रशासनिक मर्यादा पर सवाल खड़े कर सकती है।

अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर

मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद अब सबकी नजर कलेक्टर सूरजपुर की कार्रवाई पर टिक गई है, क्या मामले की जांच होगी? क्या संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा? क्या प्रशासनिक आचरण नियमों की समीक्षा होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं।

दैनिक घटती-घटना की खबर फिर बनी चर्चा का केंद्र

एक बार फिर यह साबित हुआ कि स्थानीय स्तर पर उठे मुद्दे यदि तथ्यों और सवालों के साथ सामने लाए जाएं, तो उनकी गूंज शासन स्तर तक पहुंच सकती है, 'जन्मदिन या पोस्टिंग दरबार?' शीर्षक से शुरू हुई चर्चा अब प्रशासनिक जांच और राजनीतिक मर्यादा के बड़े विमर्श में बदलती दिखाई दे रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं कंचन साहू आ. सत्यनारायण साहू, आयु लगभग-24 वर्ष, निवास का पता-डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नं0- 43 दर्रीपारा अम्बिकापुर थाना मणीपुर तहसील-अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0)। यह कि मेरे स्वयं के नाम से आधार कार्ड क्रमांक 8178 5846 2566 बना है, जिसमें मेरा नाम प्राची साहू /Prachi Sahu अंकित हो गया है, जो गलत है। मेरा सही नाम कंचन साहू / Kanchan Sahu है जो मेरे कक्षा 5वी, 8वीं एवं 10वीं के अंकसूची में अंकित है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज नाम कंचन साहू/Kanchan Sahu है और मैं इसी नाम से मैं जानी एवं पहचानी जाती हूॅ। अतएव मेरे आधार कार्ड में अंकित गलत नाम प्राची साहू/ Prachi Sahu को सुधार करते हुए मेरा सही नाम कंचन साहू/ Kanchan Sahu को दर्ज किया जाये जिस हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
कंचन साहू
निवास -डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नं0- 43 दर्रीपारा अम्बिकापुर थाना मणीपुर तहसील- अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर,छ.ग.

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम बतरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक डिलेश कुमार आ0 स्व0 शिवलाल उम्र 25 वर्ष जाति रजवार निवासी ग्राम बतरा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने पिता शिवलाल आ0 मोहन का मृत्यु दिनांक 18/12/2016 को ग्राम बतरा घर मे मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की प्रति सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मृतक शिवलाल आ0 मोहन का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21/05/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव,जिला-सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश अग्रवाल आ0/पति ओमप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी कंपनी बाजार अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - कम्पनी बाजार, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1358/6, 1359/1 रकबा 0.02, $0.01^{1/4}$, $0.00^{1/2}$, $0.00^{1/2}$, 0.02 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 22/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 02/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार अम्बष्ट आ0 संतन प्रसाद जाति कायस्थ, निवासी जोड़ापीपल केदारपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला -चोपड़ापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 9/129 रकबा $0.04^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो, अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 20/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 17/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार अम्बष्ट आ0 संतन प्रसाद जाति कायस्थ, निवासी जोड़ापीपल केदारपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - केदारपुर, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 203/5, 204/3 रकबा 0.03, 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 20/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 04/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रूपेश अग्रवाल आ0/ पति नरेश अग्रवाल जाति निवासी राममंदिर रोड़ ब्रम्हपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-करबला के पास, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3385/16 रकबा $0.04^{1/2}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 08/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

C M Y K

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:13 AM Page 5

दो दशक से एक ही दफ्तर में जमे 'प्रभावशाली स्टेनो' पर बढ़ी चर्चा

कलेक्टर बदलते ही प्रशासनिक गलियारों में फिर तेज हुई चर्चाएं,नई व्यवस्था पर सबकी नजर

मत्स्य विभाग से प्रतिनियुक्ति आख़िर कितने वर्ष के लिए,जाँच का विषय

जानकर सूत्रो का कहना है कि विगत दो दशक से भी अधिक समय से इस पद पर कार्यरत स्टेनो मध्यप्रदेश में मत्स्य विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने एन केन प्रकार से अपनी प्रतिनियुक्ति राजस्व विभाग में कराई है लेकिन प्रतिनियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है लंबे समय से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर होना कहीं ना कहीं संदेहों को जन्म देता है, क्या कारण है कि आज तक इनकी प्रतिनियुक्ति पर विभाग की भी नजर नहीं पड़ी है, जानकर कहते हैं कि स्टेनो द्वारा अपने पद और पहुँच का लाभ उठाकर दो दशक से भी अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति का लाभ नियम को दरकिनार कर उठाया जा रहा है।

मत्स्य विभाग से राजस्व विभाग में दो दशक तक प्रतिनियुक्ति भी सवाल के घेरे में...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया, 13 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया में कलेक्टर बदलने के साथ ही कलेक्ट्रेट में वर्षों से प्रभाव रखने वाले प्रभावशाली स्टेनो को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं, प्रशासनिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि संबंधित कर्मचारी पिछले दो दशक से भी अधिक समय से जिले में अलग-अलग अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण पदों पर बना हुआ है, हालांकि बीच में 2-3 वर्षों के लिए स्टेनो का तबादला सरगुजा किया गया था लेकिन सेटिंग के बदौलत फिर से स्टेनो ने कोरिया में अपना ट्रांसफर करा लिया, कर्मचारियों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्रभाव और नेटवर्क है, जिसकी वजह से लंबे समय से जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चर्चा यह भी है कि कई अधिकारी बदले, लेकिन स्टेनो की पकड़

अधिकारियों के साथ गुटबाजी और कर्मचारियों के साथ हतोत्साहित करने वाला व्यवहार

स्टेनो टू कलेक्टर अब स्थानीय निवासी बनकर रह गए हैं, जिस शकुंतला कालोनी में पूर्व कलेक्टर ऋतु सेन ने कार्यवाही की थी उसी कालोनी में स्टेनो का आलीशान बंगला है बंगला किसी बड़े अफसर से कम नहीं, जानकर बताते हैं बंगले के भीतर अधिकारियों के बंगले जैसा साज सज्जा की गई है,स्टेनो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं लेकिन हाव भाव से खुद को राजपत्रित अधिकारी से कम नहीं समझते ऐसा लोगो का कहना है, यह भी बताया जाता है कि कुछ ख़ास अधिकारियो के साथ मिलकर उनके द्वारा गुटबाजी को भारी बढ़ावा दिया जाता है ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें स्टेनो द्वारा टार्गेट कर हतोत्साहित किया जाता है।

प्रदेश के कई आईएएस अधिकारियो के साथ काम करने का अनुभव बताकर खुद को सुपर बताने में माहिर स्टेनो

स्टेनो मूल रूप से मत्स्य विभाग का कर्मचारी है और किसी ना किसी प्रकार से वह स्टेनो की कुर्सी पर अंगद के पैर की तरह चिपके हुए हैं, लंबे समय से एक ही पद पर बने रहने के कारण जाहिर सी बात है कई आईएएस अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला है लेकिन स्टेनो द्वारा खुद की तारीफ़ में इसका लाभ लेकर दुरुपयोग भी किया जाता है,खुद को सुपर बताकर अधिकारियों को स्टेनो द्वारा गुमराह भी किया जाता है।

कलेक्ट्रेट का स्थायी चेहरा बनने की चर्चा

जिला मुख्यालय में लोग इसे कलेक्ट्रेट का स्थायी चेहरा तक कहने लगे हैं, कर्मचारियों के अनुसार, वर्षों में कई प्रशासनिक बदलाव हुए, लेकिन संबंधित कर्मचारी की भूमिका और पहुंच हमेशा मजबूत बनी रही, सूत्र बताते हैं कि फाइलों की आवाजाही, अधिकारियों तक पहुंच और बाहरी लोगों से संपर्क को लेकर भी लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं, कुछ कर्मचारी इसे अनुभव का असर बताते हैं, जबकि अन्य इसे अनौपचारिक शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं।

क्या नई कलेक्टर के आने के बाद बदलेगा माहौल

नई कलेक्टर के पदभार संभालने के बाद कार्यालयीन कार्यप्रणाली और अनुशासन को लेकर गंभीरता बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है, बताया जा रहा है कि कई शाखाओं की गतिविधियों और लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच पुराने प्रभावशाली तंत्र पर भी निगाहें टिक गई हैं, कर्मचारियों में यह चर्चा है कि अब कार्यालय में व्यक्तिगत प्रभाव की जगह नियम आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकती है।

राजनीतिक और बाहरी संपर्कों की भी चर्चा

प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा का विषय है कि संबंधित स्टेनो की विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रभावशाली लोगों तक मजबूत पहुंच रही है, यही कारण है कि हर प्रशासनिक बदलाव के बाद भी उसकी स्थिति पहले जैसी बनी रही, हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिला कार्यालय में इसे लेकर लगातार कानाफूसी जारी है।

बड़ा सवाल – क्या अब होगा बदलाव?

अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था में वर्षों से जमे प्रभावशाली कर्मचारियों की भूमिका में कोई बदलाव होगा या फिर पुरानी व्यवस्था की तरह सब कुछ चलता रहेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में फिलहाल यही चर्चा सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है।

भास्कर पारा कोल खदान की खूनी रफ्तार ने ली एक और जान

-संवाददाता-

सूरजपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)। भैयाथान क्षेत्र में भास्कर पारा कोल खदान से हो रहे कोयला परिवहन के बीच एक बार फिर तेज रफ्तार भारी वाहन ने दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया, कोयला लोड ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा गया और लोगों ने खदान से दौड़ रहे भारी वाहनों की रफ्तार एवं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भैयाथान ब्लॉक मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत केवरा स्थित बिंदा फ्यूल्स के पास यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि भास्कर पारा कोल खदान से कोयला परिवहन कर रही ट्रेलर वाहन क्रमांक छ्त13ञ्ज 7666 ने मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, मृतका सलका-कसकेला क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है, वहीं मोटरसाइकिल में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से भास्कर पारा कोल खदान का संचालन प्रकाश इंडस्ट्रीज को मिला है और क्षेत्र में कोयला परिवहन शुरू हुआ है, तब से सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ गया है, ग्रामीणों का आरोप है कि संकरी और ग्रामीण सड़कों पर दिन-रात भारी ट्रेलर दौड़ रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों का कहना है कि सड़कें गांव और आम लोगों के आवागमन के लिए बनी थीं, लेकिन अब वे कोयला कॉरिडोर बनकर रह गई हैं। घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला परिवहन में लगे कई वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आम लोगों का सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया है, क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज है कि यदि समय रहते परिवहन व्यवस्था को

नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में और बड़े हादसे हो सकते हैं।

मौके पर पहुंचे बसपा नेता नरेंद्र साहू- घटना की जानकारी मिलते ही बसपा नेता नरेंद्र साहू मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की, उन्होंने कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाएं प्रशासन और खदान प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करती हैं, उन्होंने मृतक परिवार को उचित मुआवजा, घायलों के बेहतर इलाज और भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने की मांग की।

ग्रामीणों में डर और आक्रोश- घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब सड़क पर निकलना भी खतरे से खाली नहीं रह गया है, लोगों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और ग्रामीण हर समय दुर्घटना के भय में रहते हैं, ग्रामीणों ने मांग की है कि भारी वाहनों की गति सीमा तय की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण किया जाए, सड़क सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं, खदान प्रबंधन की जवाबदेही तय हो।

प्रशासन के सामने बड़ा सवाल- अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लगातार हो रहे हादसों के बाद भी भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या ग्रामीणों की सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता सिर्फ कोयला परिवहन को दी जा रही है? यह सवाल अब पूरे क्षेत्र में गूंज रहा है।

कोरिया जिले की बेटी भूमि गुप्ता बनीं सहायक संचालक,योजना,जिले में खुशी की लहर

-संवाददाता-

कोरिया,13 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिला के लिए गर्व और खुशी का क्षण सामने आया है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला कोरिया की सह संयोजक माधुरी गुप्ता की सुपुत्री कु. भूमि गुप्ता का सहायक संचालक, योजना पद पर चयन हुआ है, इस उपलब्धि के बाद परिवार सहित जिलेभर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। भूमि गुप्ता की इस सफलता को जिले के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायी उपलब्धि माना जा रहा है। परिवारजनों और शुभचिंतकों ने इसे मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम बताया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी भूमि गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि जिले की बेटियां लगातार विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर कोरिया का नाम रोशन कर रही हैं, इस अवसर पर शुभचिंतकों ने भूमि गुप्ता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी, भूमि गुप्ता को सहायक संचालक, योजना पद पर चयन होने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

जनकपुर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था ठप

अंधेरे से परेशान वार्डवासियों ने खोला मोर्चा

पार्षद मालती तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ठेकेदार पर घटिया कार्य का आरोप

-राजेन्द्र शर्मा-

जनकपुर (एमसीबी),13 मई 2026 (घटती-घटना)। नगर पंचायत जनकपुर के वार्ड क्रमांक 1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूरी तरह चरमराने से वार्डवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, लंबे समय से क्षेत्र में पसरे अंधेरे और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है, इसी कड़ी में वार्ड पार्षद मालती मदन तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की।

वार्डवासियों ने बताया कि यह क्षेत्र बाइपास रोड से जुड़ा होने के कारण यहां दिन-रात लोगों का आवागमन बना रहता है, लेकिन अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात के समय पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, इससे राहगीरों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी लगातार बनी हुई है, पार्षद मालती मदन तिवारी ने ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले जंक्शन बॉक्स में खराबी बताकर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा टाइमर सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण निकालकर ले जाए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें वापस नहीं लगाया गया, उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि इन स्ट्रीट लाइटों को लगे अभी लगभग 14 महीने ही हुए हैं, इसके बावजूद घटिया निर्माण और गुणवत्ता विहीन सामग्री के कारण लाइटें बार-बार खराब हो रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद विभाग द्वारा केवल औपचारिक मरम्मत कर खानापूर्ति की जाती है, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद फिर से लाइटें बंद हो जाती हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि कार्य में गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों का अभाव है, ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जंक्शन बॉक्स से निकाले गए उपकरणों को तत्काल वापस लगाकर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए। साथ ही पूरे निर्माण और मरम्मत कार्य की निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सरकारी राशि के दुरुपयोग और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

CMYK

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:14 AM Page 6

खनिज शाखा का अमर लिपिक टेकचंद साहू का आदेश बदले, कुर्सी नहीं!

खनिज शाखा का 'चर्चित बाबू' आखिर किसके संरक्षण में?

तबादला कागजों में,पकड़ अब भी बरकरार!

कोरिया कलेक्टोरेट का चर्चित बाबू के हटाने का आदेश आया,असर नहीं...

खनिज शाखा में आखिर किसका संरक्षण? वर्षों से जमे लिपिक पर फिर सवाल...

फाइलों में तबादला, हकीकत में वही कुर्सी!

'अमर लिपिक' की कहानी में अधिकारी बदले,व्यवस्था नहीं

क्या खनिज शाखा में नियमों से ऊपर है 'प्रभाव'?

खनिज शाखा का रहस्यमयी तबादलाः आदेश भी आया और गोपनीयता भी रही

कलेक्टर बदले,आदेश बदले...पर नहीं बदला खनिज शाखा का चेहरा...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,13 मई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिला मुख्यालय के कलेक्टोरेट में इन दिनों खनिज शाखा के एक चर्चित लिपिक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, वर्षों से एक ही शाखा में जमे इस कर्मचारी को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें और समाचार सामने आते रहे, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया, अब जब संबंधित लिपिक का तबादला आदेश सामने आया है, तब यह सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा कौन-सा संरक्षण है जिसके चलते आदेश जारी होने के बाद भी कर्मचारी की कार्यशैली और कार्यस्थल में कोई वास्तविक बदलाव नजर नहीं आ रहा।

सूत्रों के अनुसार खनिज शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 टेकचंद साहू का मार्च 2026 में स्टेनो टू कलेक्टर शाखा में तबादला किया गया था,लेकिन अब तक उनके नई शाखा में नियमित रूप से कार्य करने की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है,चर्चा यह भी है कि कागजों में पदस्थापना बदल दी गई,लेकिन व्यवहारिक रूप से वह अब भी खनिज शाखा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, यही वजह है की सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि कुर्सियां स्थायी नहीं होतीं, अधिकारी और कर्मचारी आते-जाते रहते हैं,लेकिन कोरिया जिला मुख्यालय के कलेक्टोरेट परिसर में एक ऐसी कहानी वर्षों से चर्चा का विषय बनी हुई है जिसने इस कहावत को ही चुनौती दे दी है,यहां खनिज शाखा का एक चर्चित लिपिक ऐसा भी है जिसकी कुर्सी मानो सरकारी व्यवस्था से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती दिखाई देती है, तबादले हुए, आदेश निकले,खबरें छपीं,चर्चाएं हुईं,आरोप लगे,लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वह था संबंधित लिपिक का प्रभाव और उसकी मौजूदगी। अब जब मार्च 2026 में जारी तबादला आदेश सामने आया है और यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि संबंधित लिपिक को खनिज शाखा से हटाकर स्टेनो शाखा भेजा गया था, तब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह बदलाव जमीन पर दिख क्यों नहीं रहा?

घटती घटना
सत्य के साथ...जनहित में बात...
सरगुजा - अंतर्राष्ट्रीय समाचार
अम्बिकापुर, शनिवार 13 दिसम्बर 2025
4

'अमर लिपिक' को प्रमोशन,लेकिन कुर्सी वही...

जिला प्रशासन की नीति पर फिर सवाल,क्या खनिज शाखा में सेटिंग कल्चर अमर है? या जिला खनिज शाखा में अटूट कब्जा!

प्रमोशन मिला,पोस्टिंग नहीं बदली...क्या किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण? या प्रमोशन मिला,व्यवस्था नहीं बदली...

- खनिज शाखा में वर्षों से जमे कर्मचारी को फिर से 'यथावत'आदेश, अधिकारियों की चुप्पी क्यों?
- पहले उठा था सवाल एक ही कुर्सी पर वर्षों से जमे अमर लिपिक...
- एक्सक्लूसिव 7 जिला खनिज न्यास का अमर लिपिक अब प्रमोट भी...लेकिन सीट वही क्यों?
- पदोन्नति आदेश ने और बढ़ा दिए सवाल—क्या 'यथावत पोस्टिंग'से किसी खास को संरक्षण?

-रवि सिंह-
कोरिया,12 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

अब नया मोड़: पदोन्नति आदेश में भी यथावत पदस्थापना-

जनता का सवाल: क्या यह प्रशासनिक मजबूरी या कुछ और...?

अधिकारियों की चुप्पी, सबसे बड़ा संकेत...

जिला खनिज न्यास शाखा का लिपिक वर्षों से एक ही जगह है जमा हुआ

हटाने की हिम्मत किसी अधिकारी में नहीं?

कितना सेठ बन चुका लिपिक?
आय से अधिक संपत्ति का बड़ा मामला हो सकता है उजागर

अमर लिपिक की अमर कुर्सी क्या जिला खनिज शाखा एक व्यक्ति-आधारित व्यवस्था बन चुकी है?

क्या प्रमोशन=स्थायी सेटिंग?

पूर्व रिपोर्ट से जुड़ा एक और कनेक्शन...पहले की रिपोर्ट में तीन मुख्य मुद्दे उठे थे...

चर्चाएँ: जिस कुर्सी पर सवाल थे,उस कुर्सी पर ही प्रमोशन के बाद भी टिके रहना क्या यह सामान्य है?

संभावित असर: क्या जांच की जरूरत और मजबूत हो गई?

व्यवस्था वही, कुर्सी वही,और अब प्रमोशन भी वही... क्या यही है नई प्रशासनिक नीति?

क्या यह सिर्फ संयोग है? या सोची-समझी संरचना?

क्या खनिज शाखा में कोई प्रभावी नेटवर्क सक्रिय है?

नया प्रशासन क्या करेगा?

अब जिले में नए कलेक्टर की पदस्थापना के बाद लोगों की नजर प्रशासनिक कार्यशैली पर टिकी हुई है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुराने विवादित मामलों की समीक्षा होगी और केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक स्तर पर भी प्रशासनिक आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया प्रशासन इस मामले में स्पष्ट स्थिति सामने लाएगा? क्या संबंधित कर्मचारी वास्तव में नई शाखा में कार्यरत हैं? क्या खनिज शाखा से उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हुआ? या फिर यह मामला भी धीरे-धीरे फाइलों की धूल में दब जाएगा?

वर्षों से एक ही शाखा में जमे रहने की कहानी

कोरिया जिले में प्रशासनिक हलकों में यदि किसी कर्मचारी की सबसे ज्यादा चर्चा रही है तो उनमें खनिज शाखा के चर्चित लिपिक टेकचंद साहू का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है, बताया जाता है कि वह वर्षों से जिला खनिज न्यास शाखा में पदस्थ रहे और इस दौरान विभागीय गतिविधियों, फाइलों और प्रक्रियाओं पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती चली गई, सरकारी व्यवस्था में सामान्यतः संवेदनशील शाखाओं में समय-समय पर कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है ताकि किसी एक व्यक्ति का अत्यधिक प्रभाव न बन सके, लेकिन यहां स्थिति कुछ अलग ही नजर आई, दफ्तर के गलियारों में धीरे-धीरे यह चर्चा आम हो गई कि खनिज शाखा की असली स्थायी संपत्ति फाइलें नहीं बल्कि वही चर्चित लिपिक हैं, जिन्हें हटाने की हिम्मत शायद किसी अधिकारी में नहीं दिखाई दी।

अमर लिपिक की उपाधि आखिर क्यों मिली?

स्थानीय स्तर पर प्रकाशित समाचारों में संबंधित लिपिक को अमर लिपिक तक कहा गया। यह उपाधि यूं ही नहीं मिली, दरअसल, वर्षों तक एक ही शाखा में बने रहना, लगातार विवादों में नाम आना, फिर भी प्रशासनिक कार्रवाई का असर न दिखना—इन सबने यह धारणा बना दी कि यह कोई सामान्य कर्मचारी नहीं बल्कि व्यवस्था के भीतर व्यवस्था है, दफ्तरों में मजाकिया लहजे में कहा जाने लगा कि कलेक्टर बदल सकते हैं, शाखा प्रभारी बदल सकते हैं, शासन बदल सकता है, लेकिन खनिज शाखा का यह चेहरा शायद नहीं बदलता, व्यंग्य यह भी किया जाने लगा कि यदि जिला खनिज न्यास शाखा का कोई स्थायी प्रतीक चिन्ह बनाया जाए तो उसमें सरकारी मोहर के साथ इस चर्चित कुर्सी की तस्वीर भी होनी चाहिए।

तबादला आदेश आया.... लेकिन जैसे गुप्त दस्तावेज हो

मार्च 2026 में जारी आदेश के अनुसार टेकचंद साहू, सहायक ग्रेड-2 को डीएमएफ शाखा (खनिज न्यास) से स्टेनो टू कलेक्टर शाखा में स्थानांतरित किया गया, सामान्यतः ऐसे आदेश जारी होते ही संबंधित कर्मचारी नई शाखा में कार्यभार ग्रहण करता है और व्यवस्था आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहां मामला अलग ही दिशा में चलता दिखाई दिया, सूत्रों के अनुसार आदेश जारी तो हुआ, लेकिन उसे लेकर ऐसी गोपनीयता बरती गई मानो यह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा दस्तावेज हो, लंबे समय तक आदेश सार्वजनिक रूप से चर्चा में नहीं आया, अब जब तत्कालीन कलेक्टर का तबादला हो चुका है, तब जाकर यह आदेश सामने आया और सवालों का नया दौर शुरू हो गया।

आखिर आदेश लागू हुआ भी या नहीं?

यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है, यदि कर्मचारी का तबादला हो चुका था, तो क्या उसने नई शाखा में कार्यभार ग्रहण किया? यदि किया, तो खनिज शाखा में उसकी भूमिका और प्रभाव की चर्चा अब भी क्यों हो रही है? यदि नहीं किया, तो आदेश जारी करने वाले अधिकारियों ने पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया? सूत्रों का दावा है कि व्यवहारिक रूप से स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया और संबंधित कर्मचारी का प्रभाव यथावत बना रहा, यानी कागजों में शाखा बदल गई, लेकिन वास्तविकता में व्यवस्था वही रही, सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि फाइल कहीं भी जाए, नियंत्रण वहीं रहता है जहां से व्यवस्था चलती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही चर्चा का विषय बना हुआ है।

व्यंग्य में उठ रहे तीखे सवाल, इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य का ऐसा माहौल बना दिया है कि अब लोग तंज कसते हुए पूछने लगे हैं

क्या कोरिया में तबादला आदेश केवल समाचारों के जवाब के लिए जारी होते हैं?

क्या कुछ कुर्सियों पर बैठने वालों को विशेष सुरक्षा कवच मिला हुआ है?

क्या नियम सिर्फ सामान्य कर्मचारियों के लिए हैं?

क्या खनिज शाखा में कुर्सी छोड़ने से पहले किसी अदृश्य अनुमति की आवश्यकता होती है? कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि यदि प्रशासन इस कुर्सी को संरक्षित स्मारक घोषित कर दे तो भविष्य में विवाद ही समाप्त हो जाएगा।

जिले में लंबे समय से जमे कर्मचारियों पर भी उठ रहे सवाल

यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है, जिले के कई विभागों—राजस्व, शिक्षा, ट्राइबल और खनिज शाखा—में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं, लोगों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही जगह बने रहने से कर्मचारियों का स्थानीय नेटवर्क मजबूत हो जाता है और फिर वही नेटवर्क प्रशासनिक निष्पक्षता को प्रभावित करने लगता है, यही वजह है कि अब लोग मांग करने लगे हैं कि संवेदनशील शाखाओं में नियमित अंतराल पर स्थानांतरण नीति का सख्ती से पालन कराया जाए।

अधिकारियों की चुप्पी ने बढ़ाए सवाल

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अधिकारियों की चुप्पी को लेकर हो रही है, जब किसी कर्मचारी को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित हों, शिकायतें सामने आएं, तबादला आदेश भी जारी हो जाए और फिर भी स्थिति स्पष्ट न हो—तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा कौन-सा कारण है कि अधिकारी खुलकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे? क्या वास्तव में किसी स्तर पर संरक्षण प्राप्त है? या फिर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि आदेश भी वैकल्पिक सुझाव बनकर रह गए हैं?

सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, व्यवस्था का है-

बैकुंठपुर में खनिज शाखा के चर्चित लिपिक का मामला अब केवल एक कर्मचारी के तबादले का विषय नहीं रह गया है, यह प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन चुका है, यदि आदेश जारी होने के बाद भी उसका पालन स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता, तो जनता के मन में यह धारणा और मजबूत होती है कि सरकारी व्यवस्था में कुछ लोग नियमों से नहीं बल्कि प्रभाव से संचालित होते हैं, अब देखना यह होगा कि नया प्रशासन इस मामले को सिर्फ फाइलों तक सीमित रखता है या वास्तव में व्यवस्था में बदलाव का संदेश देता है।

चोरी की घटना और बढ़ते सवाल

पूर्व में संबंधित लिपिक के निवास में चोरी की घटना भी चर्चा में रही। बताया गया कि घटना के बाद पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, इसी बात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हुईं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी जिसमें चोरी के बाद भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई? फिर चर्चाओं ने नया रूप लिया और आय से अधिक संपत्ति को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में यह मामला लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बना रहा।

खनिज शाखाः जहां फाइलों से ज्यादा चर्चा प्रभाव की

खनिज शाखा को हमेशा से संवेदनशील माना जाता है। यहां डीएमएफ राशि, खनिज अनुमति, परिवहन, भुगतान और विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े बड़े आर्थिक मामलों की फाइलें संचालित होती हैं, ऐसे विभागों में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का बने रहना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। क्योंकि धीरे-धीरे विभागीय प्रक्रियाओं पर उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, कोरिया जिले में भी यही आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं कि खनिज शाखा में कुछ लोगों की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि बिना उनकी इच्छा के फाइलों की गति तक प्रभावित होती थी, व्यंग्य में कर्मचारी यह तक कहते सुने गए कि शाखा में पदस्थ अधिकारी भले बदलते रहें, लेकिन असली सिस्टम एडमिन कोई और ही है।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला एमसीबी का बनाया गया प्रभारी,कार्यकर्ताओं में उत्साह

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी,13 मई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा जिला एमसीबी में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) जिला एमसीबी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इस नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इसे युवाओं को पार्टी से जोड़ने और संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, भाजपा संगठन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार यह नियुक्ति भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के मार्गदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के दिशा-निर्देश तथा जिला प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल की सहमति से जिला भाजपा अध्यक्ष चम्पादेवी पावले द्वारा की गई है, पार्टी नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि आशीष सिंह के संगठनात्मक अनुभव, सक्रिय कार्यशैली एवं युवाओं के बीच मजबूत पकड़ का लाभ युवा मोर्चा को मिलेगा, वे लंबे समय से भाजपा की विचारधारा को लेकर सक्रिय रूप से कार्य करते आ रहे हैं तथा संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, नियुक्ति के बाद आशीष सिंह ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका वे पूरी निष्ठा,ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे, उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाते हुए युवाओं को पार्टी की रीति-नीति एवं राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं की ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का मंच है तथा आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिला भाजपा, युवा मोर्चा एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने आशीष सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।

री-नीट को लेकर छात्रों में खुशी भी, चिंता भी

पेपर लीक और गड़बड़ियों के बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला,बिना अतिरिक्त शुल्क मिलेगा मौका

-संवाददाता-

सूरजपुर / रायपुर,13 मई 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर देशभर के विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। री-नीट को लेकर छात्रों में खुशी और गम दोनों तरह की भावनाएं देखने को मिल रही हैं।

जानकारी के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सामने आई अनियमितताओं, पेपर लीक और कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद संबंधित एजेंसियों एवं न्यायालय के निर्देश पर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, री-नीट का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर उपलब्ध कराना बताया जा रहा है, री-नीट को लेकर सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले से नीट के लिए आवेदन किया था। नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, छात्रों की प्रतिक्रिया भी मिश्रित दिखाई दे रही है। जिन अभ्यर्थियों को पहले परीक्षा में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने की आशंका थी, वे इस फैसले से खुश हैं क्योंकि उन्हें तैयारी सुधारने का एक और मौका मिल जाएगा, वहीं जिन छात्रों का प्रदर्शन पहले बेहतर रहा था, वे दोबारा परीक्षा और बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि री-नीट के बाद मेरिट सूची में बड़ा बदलाव संभव है और प्रतिस्पर्धा पहले से अधिक कठिन हो सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों को पुराने परिणामों में उलझने के बजाय नई रणनीति के साथ तैयारी करने की सलाह दी जा रही है, सूत्रों के मुताबिक परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं को ही मानें, शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि दोबारा परीक्षा कराने के निर्णय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों का भरोसा मजबूत होगा, हालांकि बदलते घटनाक्रमों के कारण छात्रों और अभिभावकों के बीच तनाव और असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, अब सभी की नजर आगामी आधिकारिक घोषणा और री-नीट के आयोजन पर टिकी हुई है।

C M Y K

अब काम मांगने में नहीं शरमाता, हमारा स्ट्रगल फिल्म हिट होने के बाद भी खत्म नहीं होता : पुलकित सम्राट

'फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल के दौरान आपको लगता है कि सबसे मुश्किल काम पहला ब्रेक मिलना है, मगर मेरा यकीन मानिए उससे भी ज्यादा मुश्किल है लगातार काम मिलते रहना।' यह कहना है एक्टर पुलकित सम्राट का। फिल्म 'बिट्टू बॉस' से फिल्मी करियर शुरू करने वाले पुलकित ने अपने इस सफर में सुपरहिट 'फुकरे' फ्रेंचाइजी से लेकर 'डॉली की डोली' और 'पागलपंती' जैसी चर्चित फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, मगर पुलकित का कहना है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए लगातार मेहनत करने रहनी पड़ती है...

'फुकरे' सुपरहिट होने के बाद भी काम की झड़ी नहीं लग गई

पुलकित की नई वेब सीरीज 'ग्लोरी' सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है। ऐसे में, एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए की गई जद्दोजहद को याद करते हुए पुलकित बताते हैं, 'इंडस्ट्री में हमारा कोई गॉडफादर नहीं था। हम आउटसाइडर थे और यहां अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन जगह आप तभी बना पाएंगे, जब आपको कुछ काम मिलेगा। इसलिए, पहले तो वो काम मिलना जरूरी है। उस पर आपको लगता है कि सबसे मुश्किल चीज यह पहला काम मिलना ही है। आप सोचते हैं कि बस एक ब्रेक मिल जाए, लेकिन मेरा यकीन करिए कि आपको लगातार काम मिलते रहना सबसे मुश्किल चीज है और उसके लिए आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आपको जाकर लोगों को खुद को बतौर प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। वह बहुत जरूरी है।'

'काम मांगिए और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है'

'खुशकिस्मती से आज हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म हैं कि कोई कलाकार ये बोले कि मुझे काम नहीं मिल रहा तो मेरे हिसाब से वो काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि आज काम करने की बहुत सारी जगहें हैं। मैंने जब शुरुआत की थी, तब ऐसा नहीं था। आज बहुत सारे मंच हैं। बस आप घर से निकलिए, लोगों से बोलिए कि मुझे काम करना है। काम मांगिए और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है, जो पहले मुझे लगता था कि मैं दिखा तो दिया। 'फुकरे' कर ली, फिल्म सुपरहिट हो गई, अब तो कल से लाइन लग जाएगी लेकिन कोई लाइन नहीं लगती। यह सच्चाई है। आपके लिए दरवाजे बेशक खुल जाते हैं पर उस दहलीज को पार करके अंदर जाना आपका काम है और मुझे लगता है कि सेट से ज्यादा काम सेट के बाहर रहता है।'

मैं जैसा पहले था, उस पर गर्व नहीं

सीरीज में पुलकित अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करते हैं। असल जिंदगी में उन्होंने अपनी किसी खामी पर जीत पाई है? यह पर उन्होंने बताया, 'मुझमें बहुत खामियां थीं। एक वक्त पर मैं अपने आप का एक ऐसा वर्जन था जिस पर मुझे आज बिल्कुल गर्व नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो मुझे धीरे-धीरे समझ में आई। जब मैं घर से निकला, अकेले उड़ान भरनी शुरू की, ठोकरें खाई तब मुझे समझ आई कि जीने का ये सही तरीका नहीं है। शुरू में हमें ज्यादा समझ नहीं होती है। आप कभी मजाक में किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद उसे बुरी लगे। आज समझ में आता है कि नहीं यार, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या मुझे सेट पर ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था या मैं इस सिचुएशन को बिना गुस्से के भी हैंडल कर सकता था। तब जब लोग आपको बोलते भी हैं न तो भी समझ में नहीं आता है, जब तक आपके पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ती।'

बॉक्सिंग ने सिखाया जिंदगी का सबक

वहीं, सीरीज में बॉक्सर की भूमिका के लिए की तैयारी पर वह बताते हैं, 'इसमें मेरा किरदार एक प्रोफेशनल बॉक्सर का है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ी। बॉक्सिंग को समझना पड़ा और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तब मुझे समझ आया कि बॉक्सिंग केवल फिजिकल नहीं है, यह एक माइंड गेम भी है। यह एक शतरंज के खेल की तरह है जहां आप रिंग में अपने विरोधी का दिमाग पढ़ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं और मैं कहूंगा कि बॉक्सिंग ने मुझे ये सिखाया कि उन्हीं नियमों को अपनी असल जिंदगी में भी कैसे उतार सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में उससे कैसे निकल सकते हैं। हां, कुछ पंचेज जरूर आपके चेहरे पर पड़ेंगे, पर वही पंचेज आपको उनको मिस करना भी सिखाएगा और एक काउंटर पंच मारना भी सिखाएगा तो इसने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इससे पहले मेरे लिए फिजिकली फिट होने का मतलब सिर्फ फिट दिखना था, फिजिकली फिट महसूस करना नहीं था। एक फिट इंसान की तरह सोचना नहीं था, बॉक्सिंग ने मुझे यह सिखाया कि सिर्फ फिजिकली फिट दिखना काफी नहीं है। ओवरऑल वेलनेस जरूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना है और उसे मैं अपने जिंदगी में उतार रहा हूं।'

घुंघराले बालों से थी नफरत, अब वही बनी अनुपमा परमेश्वरन की पहचान

दक्षिण भारतीय फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन आज अपनी शानदार अभिनय क्षमता के साथ-साथ खूबसूरत घुंघराले बालों के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने दिल की बात फैंस के साथ साझा की। अनुपमा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अपने कर्ली हेयर को फ्लॉन्ट किया। इसके साथ उन्होंने एक भावुक और प्रेरणादायक नोट भी लिखा। अभिनेत्री ने बताया कि बचपन और शुरुआती दिनों में वह अपने घुंघराले बालों को छिपाने की कोशिश करती थीं। उन्हें लगता था कि उनके बाल दूसरों की तरह सीधे और सामान्य होने चाहिए। यही वजह थी कि वह बार-बार अपने बालों को सीधा करने और बदलने की कोशिश करती रहती थीं। अभिनेत्री ने लिखा कि समय के साथ उन्होंने खुद को समझना और अपनाना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वही उनकी असली पहचान और खूबी है। अनुपमा के मुताबिक, अब उनके घुंघराले बाल उनकी सबसे पसंदीदा चीजों में शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है, जब लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें देखकर उन्होंने भी अपने प्राकृतिक घुंघराले बालों को अपनाना शुरू किया। अभिनेत्री ने कहा कि खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना बेहद

शक्तिशाली एहसास होता है और यही आत्मविश्वास दूसरों को भी खुद से प्यार करना सिखाता है। अनुपमा परमेश्वरन दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी नेचुरल एक्टिंग, मासूम अंदाज और गर्ल-नेक्स्ट-डोर इमेज के लिए काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म 'प्रेमम' से मिली लोकप्रियता के बाद उन्होंने 'कार्तिकेय 2' और 'टिल्लू स्क्वायर' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुपमा जल्द ही तेलुगु रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'क्रेजी कल्याणम' में नजर आएंगी, जिसका निर्देशन बदरप्पा गजुला कर रहे हैं। इसके अलावा वह निर्माता प्रेरणा अरोड़ा की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में भी दिखाई देंगी, जिसकी शूटिंग मई 2026 में शुरू होने वाली है।

14 मई को रिलीज होगी तृषा कृष्णन की करुप्पु

तमिल सिनेमा की अभिनेत्री तृषा कृष्णन बहुप्रतीक्षित फिल्म करुप्पु का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया। इस फिल्म में अभिनेता सूर्या मुख्य भूमिका में हैं, जबकि आरजे बालाजी ने न केवल इसका निर्देशन किया है, बल्कि खलनायक के किरदार में भी नज़र आएंगे। फिल्म 14 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। करुप्पु एक एक्शन से भरपूर कोर्टरूम ड्रामा है, जो एक लंबे समय से लंबित और उपेक्षित पड़े मामले पर आधारित है। ट्रेलर में कानूनी लड़ाई, तीव्र संवाद और दमदार एक्शन दृश्यों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को न्याय और प्रतिशोध के गहन विषय से रूबरू कराएगा। फिल्म का निर्देशन आरजे बालाजी ने बड़ी कुशलता से किया है, जिन्होंने कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया है। ट्रेलर करुप्पु में सूर्या को दो भिन्न और प्रभावशाली अवतारों में प्रस्तुत करता है। एक तरफ वह अदालत के भीतर अपनी बात को मजबूती से रखते हुए वकील की भूमिका में दिखते हैं, तो दूसरी तरफ वह सड़कों पर न्याय के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। वह एक ऐसे मामले को अपने हाथों में लेते हैं जिसे वर्षों से अनदेखा किया जा रहा था। उनका किरदार कानूनी पेचीदगियों से जूझने के साथ-साथ शारीरिक टकरावों में भी शामिल होता है, जो फिल्म की गहनता और रोमांच को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि न्याय की लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी एक अलग तरह का संघर्ष जारी है। फिल्म की कहानी एक गंभीर पृष्ठभूमि के साथ शुरू होती है, जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पोती न्याय की उम्मीद में बार-बार अदालत के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तृषा कृष्णन भी एक वकील की सशक्त भूमिका में हैं, जो उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं। हालांकि, उन्हें डिफेंस काउंसिल यानी आरजे बालाजी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो अपने किरदार में पूरी तरह से खलनायक के रंग में रंगे हुए दिखते हैं। उनका टकराव फिल्म के ड्रामा को और बढ़ाता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सूर्या का किरदार करुप्पु इसमें प्रवेश करता है। वह इस अनदेखे मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ और आश्वस्त दिखाई देता है। उसका संघर्ष केवल कानूनी प्रणाली तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह रास्ते में आने वाले हर अवरोधक से भिड़ने को तैयार रहता है। ट्रेलर में उसके कोर्ट में तीखी बहस और बाहर शारीरिक झड़पों की झलक साफ तौर पर दिखाई गई है।

खेल समाचार

सीएसके के पास प्लेऑफ में पहुंचने का शानदार मौका, आरआर काफी हद तक सूर्यवंशी पर निर्भर : चावला

नई दिल्ली, 13 मई 2026। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पास इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने का बेहतरीन मौका है। लगातार तीन जीत के साथ पांच बार की चैंपियन टीम ने टॉप-4 की दौड़ के लिए जरूरी मोमेंटम हासिल कर लिया है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 11 में से 5 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने शुरुआती तीन हार के बाद जीत की लय हासिल करते हुए अगले 8 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए। फिलहाल इस टीम के पास 12 अंक हैं। प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष चार टीमों पर नजर डालें, तो गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 14-14 अंक हैं। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर मौजूद है। पीयूष चावला ने 'जियोस्टार' पर कहा, 'मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक अच्छा मौका है। हम टी20 क्रिकेट में मोमेंटम के बारे में बहुत बात करते हैं, और पिछले तीन मैच जीतने के बाद उनके पास वह मोमेंटम है। वे सच में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके बल्लेबाज अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह गेंदबाज हैं- अंशुल कंबोज, स्पिन जोड़ी नूर और अकील हुसैन और मिडिल ओवर्स में जेमी ओवरटन, जो असली फर्क पैदा कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की थी। सीएसके ने साल 2018 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा का स्कोर चेज किया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पावरप्ले के खेल तक 1 विकेट गंवाकर 97 रन बना लिए थे, जो आईपीएल में उनका दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर था। इस दौरान उर्विल पटेल ने महज 9 गेंदों में 42 रन बना लिए। बाद में उन्होंने महज 13 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा करते हुए 65 रन की पारी खेली। इस मुकाबले में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 42 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे (7 गेंदों पर 15*) और प्रशांत वीर (12 गेंदों पर 17*) ने मैच को फिनिशिंग टच दिया। पीयूष चावला ने कहा, '200 का स्कोर अब आम बात हो गई है लेकिन जब आप टीमों को उससे कम स्कोर तक सीमित रखते हैं, तो बल्लेबाजों को भी थोड़ी राहत मिलती है।

मोहन बागान क्लब के पूर्व अध्यक्ष टूटू बोस का 78 साल की उम्र में निधन, सीएम सुवेंदु अधिकारी ने जताया शोक

कोलकाता, 13 मई 2026। मोहन बागान फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय फुटबॉल के सबसे प्रभावशाली खेल प्रशासकों में से एक टूटू बोस का कोलकाता में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और मोहन बागान क्लब ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, 'मोहन बागान क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व संसद सदस्य और सीनियर खेल प्रशासक स्वपन साधन बोस (टूटू बसु) के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है।' उन्होंने लिखा, 'मोहन बागान क्लब और टूटू बसु एक-दूसरे के पूरक थे। कई सालों तक खेल प्रशासन में उनका असाधारण योगदान हमेशा यादगार रहेगा। उनका नेतृत्व, विजन और खेल के लिए सच्चा प्यार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मैं उनके दुखी परिवार, प्रियजनों, शुभचिंतकों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति

अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।' मोहन बागान सुपर जायंट ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आपकी विरासत हमेशा मोहन बागान का हिस्सा रहेगी। रेस्ट इन पीस, टूटू बोस।' टूटू बोस का वास्तविक नाम स्वपन सदा बोस था। वह राज्यसभा के सांसद रहे थे। उनके नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल ने बदलाव का दौर देखा। टूटू बोस पहली बार 1989-90 में मोहन बागान एसी के पोर्टफोलियो होल्डर बने। यह भारतीय क्लब फुटबॉल में सबसे लंबे अध्यक्षीय कार्यकाल में से एक रहा। उन्होंने फीफा क्लब टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में भी काम किया, जिससे मोहन बागान और भारतीय फुटबॉल को वैश्विक प्रशासन चर्चाओं में एक आवाज मिली। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने 2017 में अपना पद छोड़ दिया था। मई 2022 में, उन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया था। उनके नेतृत्व में मोहन बागान नेशनल टूर्नामेंट में टॉप दावेदार बना रहा। टीम ने अपनी ब्रांड वैल्यू और फैन एंगेजमेंट को बढ़ाया और आधुनिक फुटबॉल के हिसाब से खुद को ढालते हुए एक हेरिटेज क्लब के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखी। अप्रैल 2025 में, टूटू बोस ने मोहन बागान में सभी पदों से आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली थी।

नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप : क्वार्टर फाइनल में पहुंची गुहन-संदेश की जोड़ी

चेन्नई, 13 मई 2026। नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में बुधवार को गुहन सेंथिलकुमार और संदेश पीआर ने राउंड ऑफ 16 में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को सीधे गेम में 11-1, 11-2 से शिकस्त दी। इसी के साथ तमिलनाडु की जोड़ी ने मेंस डबल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इंडियन स्क्वैश एकेडमी में तमिलनाडु की टीम ने शुरू से ही रैलियों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए मुकाबले को निर्णायक रूप से समाप्त किया। शुभम और वेदांत पटेल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस जोड़ी ने अक्षय दीपक और पार्थिबन को सीधे गेम में 11-8, 10-12 और 11-2 के स्कोर से हराया। मैथ्यू गॉडविन और नवनीत प्रभु ने विदिक करकाशे और यश सोनवानी के खिलाफ 11-4, 11-6 की आसान जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रवि दीक्षित और विकास मेहरा भी आगे बढ़े, उन्होंने अजिंक्य शिंदे और ओंकार अवहद को 11-3, 11-4 के स्कोर से आसानी से हरा दिया। विमेंस डबल्स ग्रुप-बी राउंड-रॉबिन में, जेनेट विधि और पूजा आरती तब आगे बढ़ीं, जब क्रिया सरवनन और नंदिकाश्री मैच से रिटायर हो गईं।

पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले अकेले अभ्यास करते दिखे पांड्या

मुंबई, 13 मई 2026। मुम्बई इंडियंस टीम का प्रदर्शन आईपीएल के इस सत्र में अच्छा नहीं रहा है और टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गयी है। टीम को आज बचे हुए लीग मैच में पंजाब किंग्स से खेलना है। मुम्बई की टीम इस मैच में जीत के साथ ही अपना खोया मनोबल हासिल करने का प्रयास करेगी। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी इस सत्र में अच्छा नहीं रहा और वह आलोचकों के निशाने पर हैं।

पांड्या फिट नहीं होने के कारण पिछले दो मैचों से बाहर थे। अब उनका लक्ष्य आज पंजाब किंग्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर लय हासिल करना चाहेंगे। इसी को देखते हुए पांड्या अकेले ही नेट्स में अभ्यास करते दिखे। इससे साफ है कि वह पंजाब के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। इससे टीम और प्रशंसकों के बीच उम्मीदें जगी हैं। हालांकि फ्रेंचाइजी ने अभी तक उनकी उपलब्धता पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

टेनिस खिलाड़ी पुरस्कार राशि के मामले में अब पीछे नहीं हटेंगे : पेगुला

रोम, 13 मई 2026। टेनिस जगत में खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अब इस अभियान का नेतृत्व कर रही अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने कहा है कि खिलाड़ी अब अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पेगुला ने कहा कि यह सही समय है जब खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के कुल राजस्व में एक बड़ा मिलना चाहिए। वहीं इससे पहले विश्व नंबर-1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर और महिला वर्ग की नंबर-1 खिलाड़ी एरीना सबालेंका ने भी कहा था कि पुरस्कार राशि बढ़ायी जानी चाहिये। गई है। पेगुला खिलाड़ियों को इस मामले को लेकर एक मंच पर लाने का प्रयास भी कर रही हैं। । उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से इस मामले में सीधे बात करने और उन्हें एकसाथ लाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। पेगुला ने कहा, मैं किसी भी

खिलाड़ी के पास जाकर पूछ सकती हूं कि क्या वह इस मामले में हमसे सहमत है या नहीं । साथ ही कहा कि कुछ खिलाड़ी शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी पूरी तरह से समर्थन में हैं। वह पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ियों से लगातार संपर्क कर रही हैं और उन्हें इस अभियान में शामिल कर रही हैं। पेगुला ने संकेत दिया कि अन्य प्रमुख पेशेवर खेलों की तुलना में टेनिस खिलाड़ियों को उनके योगदान के बदले काफी कम हिस्सा मिलता है। उन्होंने एनएफएल (नेशनल फुटबॉल लीग) और एनएचएल (नेशनल हॉकी लीग) जैसी लीगों का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें खिलाड़ियों को लीग के कुल राजस्व का लगभग 50 फीसदी हिस्सा मिलता है। इसके विपरीत, अधिकतर टेनिस टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों का यह हिस्सा बहुत कम रहता है। खिलाड़ियों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, फ्रेंच ओपन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भी खिलाड़ियों को कुल राजस्व का 14.9 फीसदी से भी कम हिस्सा मिलता है, जो कि अन्य खेलों की तुलना में एक बड़ा अंतर है। वहीं पिछले सप्ताह बेलारुस की, एरीना सबालेंका ने भी इस मामले को उठाया था और कहा था कि यदि खिलाड़ियों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता।

14 MAY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11_Layout 2 5/14/2026 12:14 AM Page 8

पीएससी 2003 घोटाला : भ्रष्टाचार साबित,फिर भी समझौते की बात क्यों?

पीएससी 2003 विवाद में नया मोड़,क्या अब समझौते से दब जाएगा घोटाले का सच?

पीएससी घोटाले में फैसला टालने का नया रास्ता या न्याय की नई प्रक्रिया?

विशेष लोक अदालत में सुलह की पहल से फिर गरमाया मामला

23 साल बाद भी अधूरा न्याय! पीएससी 2003 घोटाले में अब 'समझौते' की पहल पर उठे सवाल

23 साल से लंबित पीएससी घोटाला, क्या फैसले से पहले ही खत्म हो जाएगा पूरा कार्यकाल?

हाई कोर्ट ने माना घोटाला,सुप्रीम कोर्ट में आपसी सुलह से सुलझाने की मांग?

पीएससी भर्ती घोटाला: न्याय मिलेगा या समय ही बन जाएगा सबसे बड़ा बचाव?

भर्ती घोटाले से लेकर बड़े पदों तक...अब लोक अदालत में समाधान की तैयारी

52 अपात्र चयनित,योग्य बाहर...फिर भी 23 साल बाद फैसला अधर में

पीएससी 2003: सिस्टम पर लगे दाग का जवाब कौन देगा?

घोटाला प्रमाणित,कार्रवाई अधूरी...आखिर किसे बचा रही लंबी कानूनी प्रक्रिया?

वर्षा डोंगरे
याचिकाकर्ता

संतन देवी जॉंगड़े
वर्तमान कलेक्टर, एमसीबी

संजय चंदन त्रिपाठी
तत्कालीन कलेक्टर, कोरिया

न्यूज डेस्क

रायपुर,13 मई 2026।
एमसीबी/कोरिया/रायपुर 13 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी 2003 भर्ती घोटाला में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है, करीब दो दशक पुराने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत के जरिए 'समाधान' की कोशिश शुरू हुई है, लेकिन इस पहल ने जितने सवाल हल नहीं किए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सच में समाधान की प्रक्रिया है या फिर फैसले को और लंबा खींचने की रणनीति?

2003 का घोटाला,2026 तक अधर में न्याय

छत्तीसगढ़ पीएससी 2003 भर्ती घोटाला राज्य के सबसे चर्चित भर्ती विवादों में गिना जाता है, आरोप लगे थे कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी,अंक हेराफेरी,नियमों का उल्लंघन और अपात्र अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया,मामले में मुख्य याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे ने वर्ष 2006 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी,लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को सही माना था,हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी हुई और नियमों को ताक पर रखकर कई अपात्र उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया,कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरी चयन सूची संशोधित कर नई सूची जारी करने का आदेश भी दिया था,यही वह फैसला था,जिससे कई प्रभावशाली अधिकारियों की कुर्सियां खतरे में आ गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, फिर वर्षों तक सुनवाई

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई प्रभावित अधिकारियों और चयनित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,इनमें संजय चंदन त्रिपाठी सहित कई अधिकारी शामिल बताए जाते हैं,सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद मामला वर्षों तक लंबित चलता रहा,अब अचानक इस मामले को विशेष लोक अदालत के जरिए 'आपसी सहमति' से सुलझाने की पहल ने नई बहस छेड़ दी है, सूत्रों के मुताबिक, याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे समेत अन्य पक्षकारों को समाधान समारोह के लिए बुलाया गया है, मुंगेली और कबीरधाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में उपस्थित होने के नोटिस भी जारी किए गए हैं,लेकिन वर्षा डोंगरे ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट पहले ही उनके पक्ष में फैसला दे चुका है और राज्य सरकार को उस आदेश का पालन करना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला,अब 'समाधान' की कोशिश

हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित अधिकारियों और उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इनमें कई ऐसे अधिकारी भी शामिल बताए जाते हैं जो वर्तमान में प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, सूत्रों के अनुसार, कोरिया के तत्कालीन कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी तथा वर्तमान एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े जैसे नाम भी उन प्रभावित अधिकारियों में बताए जा रहे हैं, जिनकी नियुक्तियां इस विवाद से जुड़ी रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवाद निपटाने की पहल की जा रही है, इसके लिए वर्षा डोंगरे सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने कहा गया है।

'समय काटने' की चर्चा क्यों?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में एक नई चर्चा तेज हो गई है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पूरी प्रक्रिया केवल समय निकालने की कोशिश है? दरअसल, हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित कई अधिकारी अब अपने करियर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, कुछ सेवानिवृत्ति के करीब हैं, तो कुछ ऊंचे प्रशासनिक पदों तक पहुंच चुके हैं, इसी वजह से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि यदि मामला लंबा चलता रहा तो कई अधिकारी सेवा समाप्ति तक सुरक्षित रह सकते हैं, यही कारण है कि लोक अदालत के जरिए 'सुलह' की कोशिश को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है।

क्या घोटाले से जुड़े अधिकारियों के हाथ में ही प्रशासन?

मामले की सबसे संवेदनशील बात यह है कि जिन अधिकारियों के नाम कभी पीएससी भर्ती विवाद में सामने आए थे, उनमें से कई वर्षों तक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते रहे, यही कारण है कि आम लोगों के बीच यह सवाल भी उठता रहा कि आखिर जिन नियुक्तियों पर ही सवाल खड़े हुए, क्या उन्हीं अधिकारियों को जिलों और प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती रही? हालांकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जब तक न्यायालय कोई अंतिम आदेश नहीं देता, तब तक किसी को दोषी मानना कानूनी रूप से उचित नहीं कहा जा सकता।

एसीबी जांच में भी हुई थी पुष्टि

इस मामले को और गंभीर इसलिए माना गया क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच में भी अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी, हाई कोर्ट के आदेश में कई ऐसे नाम सामने आए थे, जिनका चयन कम अंक होने के बावजूद हुआ, वहीं कई पात्र अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर कर दिए गए थे, कोर्ट के अनुसार, कुल 52 ऐसे उम्मीदवार थे जो इंटरव्यू के पात्र ही नहीं थे, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया। वहीं 17 योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए थे, यदि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दोबारा स्केलिंग कर नई चयन सूची लागू होती, तो दो दर्जन से अधिक अधिकारियों की नियुक्तियां प्रभावित हो सकती थीं। इनमें से कुछ अधिकारी बाद में आईएएस स्तर तक भी पहुंच गए।

23 साल बीते, अब बचे हैं सिर्फ 10 साल...क्या न्याय की प्रतीक्षा में वही भी गुजर जाएंगे?

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी 2003 भर्ती घोटाले को अब 23 साल गुजर चुके हैं, जिन अधिकारियों की नियुक्तियों पर सवाल उठे, उनमें से कई पूरा कार्यकाल निकाल चुके हैं और अब मुश्किल से 8 से 10 साल की सेवा शेष बची है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या न्याय की प्रतीक्षा में यह बचा हुआ समय भी निकल जाएगा? मामले में हाई कोर्ट भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को प्रमाणित कर चुका है, एसीबी जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हो चुकी है, इसके बावजूद मामला वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब विशेष लोक अदालत के जरिए 'आपसी सहमति' से समाधान की बात ने पूरे प्रकरण को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

घोटाला साबित होने के बाद 'समझौते' की गुंजाइश क्यों?

पीएससी 2003 मामला अब किसी दो व्यक्तियों के निजी विवाद का विषय नहीं रह गया है, यह मामला पूरे सिस्टम की पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रशासनिक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, जब हाई कोर्ट अपने फैसले में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि कर चुका है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अब 'आपसी सहमति' किस बात की? क्या भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे मामलों का समाधान समझौते से हो सकता है?

क्या समय ही सबसे बड़ा बचाव बन गया?

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह चर्चा भी तेज है कि कहीं लंबी कानूनी प्रक्रिया ही सबसे बड़ा बचाव तो नहीं बन गई? 23 वर्षों में कई अधिकारी ऊंचे पदों तक पहुंच गए, कई सेवा के अंतिम दौर में हैं, ऐसे में यदि फैसला आने में और वर्षों लगते हैं, तो क्या वास्तविक जवाबदेही तय हो पाएगी? यही वजह है कि लोक अदालत के जरिए समाधान की कोशिश पर भी सवाल उठ रहे हैं।

यह सिर्फ भर्ती घोटाला नहीं,व्यवस्था पर सवाल है

पीएससी 2003 विवाद ने केवल कुछ नियुक्तियों को नहीं, बल्कि पूरी चयन प्रणाली की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा किया था, योग्य अभ्यर्थियों का बाहर रह जाना और कम अंक पाने वालों का चयन होना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि व्यवस्था पर चोट माना गया, इसलिए अब यह मामला केवल नौकरी या पद बचाने का नहीं, बल्कि यह तय करने का भी है कि क्या व्यवस्था में हुए कथित भ्रष्टाचार पर समय के साथ पर्दा डाल दिया जाएगा या फिर जवाबदेही तय होगी।

अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

करीब 23 साल पुराने इस मामले में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, एक तरफ प्रभावित अभ्यर्थी वर्षा डोंगरे के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चयनित अधिकारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इतने वर्षों बाद भी पीड़ित अभ्यर्थियों को वास्तविक न्याय मिल पाएगा, या फिर यह मामला भी भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबित फाइलों की भीड़ में धीरे-धीरे इतिहास बन जाएगा?

डिस्क्लेमर

यह समाचार विभिन्न न्यायालयीन दस्तावेजों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं, मीडिया रिपोर्ट्स एवं संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर तैयार किया गया है, पीएससी 2003 भर्ती घोटाला मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है तथा अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाना शेष है, समाचार में उल्लेखित किसी भी अधिकारी, व्यक्ति या पक्ष को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दोषी घोषित नहीं किया गया है, समाचार का उद्देश्य केवल जनहित से जुड़े विषयों को प्रस्तुत करना है, किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करना नहीं, यदि किसी पक्ष को समाचार में प्रकाशित तथ्यों पर आपत्ति हो तो उनका पक्ष भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

रायगढ़...सट्टा सिंडिकेट के 3 आरोपी अरेस्ट,1 करोड़ कैश जब्त

मास्टरमाइंड अवैध कमाई कारोबारियों के यहां रखता था,बाप-बेटा व्हाइट मनी में बदलते

रायगढ़,13 मई 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा केस में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड सट्टे की कमाई को अलग-अलग कारोबारियों के यहां छिपाकर रखता, फिर उसे हवाला चैनल के जरिए आगे ट्रांसफर करता था। वहीं, गिरफ्तार बाप-बेटे सट्टे से मिले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते थे। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड़ 2 लाख 81 हजार 300 रुपए कैश, एक नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया है। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 1 करोड़ 3 लाख 86 हजार 300 रुपए की संपत्ति जब्त की है। जानकारी के अनुसार, 26 अप्रैल को साइबर सेल, कोतवाली पुलिस और घरघोड़ा थाना की संयुक्त टीम ने शहर और घरघोड़ा क्षेत्र में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा नेटवर्क पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सोनू देवांगन (21), हर्षित देवांगन (24), भरत गोयल (22), गौतम भोजवानी (26), लक्ष्मीनारायण सिदार (28) और सागर गुप्ता (27) शामिल हैं। सभी आरोपी अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े हुए थे। रायगढ़ पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और कैश जब्त की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि पूरा सट्टा नेटवर्क रायगढ़ के करन चौधरी (29) और जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार के इशारे पर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और पैसों के लेन-देन की जांच शुरू की।

बीजापुर में नक्सली डंपों से 65 लाख नकद बरामद

पुलिस ने 32 हथियार और विस्फोटक जब्त की,अब तक 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली

बीजापुर,13 मई 2026। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगलों में छिपाए गए डंपों से भारी मात्रा में नकदी, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बीजापुर पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने अलग-अलग ठिकानों से 65.52 लाख रुपए नकद, 32 घातक हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार, अब तक की कुल कार्रवाइयों में 7.2852 करोड़ रुपए नकद और 8.20 किलोग्राम सोना सहित करीब 20.0852 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की जा चुकी है।

'नक्सलमुक्त बीजापुर' अभियान के तहत कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के 'नक्सलमुक्त बीजापुर' अभियान के तहत पिछले एक महीने से सुदूर इलाकों में सघन सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत खुफिया तंत्र की मदद से के छिपे हुए नक्सली डंपों का पता लगाया गया।

एलएमजी, एसएलआर और कार्बाइन जैसे हथियार बरामद

बरामद हथियारों में 1 एलएमजी, 4 एसएलआर, 1 कार्बाइन, 5 .303 रायफल, 1 .315 रायफल, 5 सिंगल शॉट बंदूकें, 4 बारह बोर बंदूकें, 7 बीजीएल लॉन्चर और 1 पिस्टल शामिल हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। इनमें 33 एके-47 कारतूस, 219 एसएलआर कारतूस, 181 .303 कारतूस, 118 .315 कारतूस और 84 बीजीएल सेल शामिल हैं।

140 किलो विस्फोटक मौके पर नष्ट

पामेड़ थाना क्षेत्र के कवरगुट्टा जंगल और नेशनल पार्क इलाके से सुरक्षा बलों ने 140 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया बरामद किया। सुरक्षा कारणों से इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, टूल्स और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है।

माओवादियों की सप्लाई चेन को बड़ा नुकसान

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की लॉजिस्टिक सप्लाई, हथियार आपूर्ति और आईईडी निर्माण क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 से अब तक 517 हथियार और 1092 आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2025-26 में अब तक 461 हथियार जब्त किए गए हैं।

CSMCL ओवरटाइम भुगतान घोटाला सीडीएल के वाइस प्रेसिडेंट गिरफ्तार

अरुणपति त्रिपाठी के संपर्क में था उदय राव ढेबर को जाता था कमीशन,8 आरोपी गए जेल

रायपुर,13 मई 2026। रायपुर में सामने आए CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीडीएल के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) एन. उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि ओवरटाइम और बोनस की बिलिंग का पूरा काम उदय राव के निर्देश पर किया जाता था। इस प्रक्रिया में कमीशन को लेकर वह अरुणपति त्रिपाठी से संपर्क में रहता था। अरुणपति के निर्देशों के बाद यह रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाई जाती थी। वहीं, इस मामले में पहले से गिरफ्तार सात आरोपियों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद विशेष न्यायालय ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैनपावर सप्लाई का काम रिकॉर्ड में ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड के नाम पर दर्ज था, लेकिन असल में इसका संचालन एन. उदय राव कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि वह

फील्ड मैनेजमेंट, बिलिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था और भुगतान से जुड़े काम सीडीएल से जुड़ी कंपनी एनकेजेए की ओर से संभालते थे। EOW-ACB के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त चार दिनों के काम के भुगतान के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को करीब 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम के नाम पर करीब 101.20 करोड़ रुपए, बोनस के रूप में 12.21 करोड़ रुपए और अतिरिक्त चार दिनों के काम के बदले 54.46 करोड़ रुपए शामिल हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)